04 - कर्तव्य बोध का उज्वल पक्ष

05 - इस बार ट्रम्प की भारत से विदाई तय है

06 - तीसरी फसल से बढ़ी किसानों की आय, आज समर्थन मूल्य में मूँग...

07 - आयुष्मान में हमीदिया के अटके 6.6 करोड़ रुपए पास

A Daily News Magazine
भोपाल
शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 330, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

बिहार चुनाव : जनसुराज सहित नए दलों का क्या है गणित?

मोहन कुमार

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई नई राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। नए खिलाड़ियों के आने से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है, जिससे चुनाव पर असर पड़ सकता है। ये नए खिलाड़ी चुनाव परिणाम को बनाने-बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन सुराज के गठन के बाद, दो और राजनीतिक दल का गठन हुआ। अभी तक किसी भी पार्टी ने बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने की घोषणा नहीं की है। ये पार्टियां हैं- पूर्व कांग्रेस नेता आईपी गुप्ता की इंडियन इंकलाब पार्टी (आईआईपी), और सिविल सेवा से इस्तीफा देने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे की हिंद सेना पार्टी।

'वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद कहते हैं कि हम नई पार्टियों को सिरे से नहीं नकार सकते। नई पार्टियों के लिए जगह है- इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली है। इन पार्टियों के गठन के पीछे दो फैक्टर हैं, पहला- राजनीतिक महत्वाकांक्षा और दूसरा क्षेत्रवाद। ये दोनों चीजें नई पार्टियों के लिए प्लेटफॉर्म का काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) जैसी मेनस्ट्रीम पार्टियों में सैचुरेशन की स्थिति भी देखने को मिल रही है। जिसका नतीजा है कि जन सुराज जैसी नई पार्टियां आ रही हैं।'

पूर्व आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह ने भी आप सबकी आवाज (राष्ट्रीय) नाम से पार्टी का गठन किया था। हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का जन सुराज में विलय कर दिया। इसके अलावा कुछ और पार्टियां भी हैं, जो पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन बिहार की सियासत में नई मानी जाती है। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं, 'गंभीर राजनीति करने वालों में एक ही नई पार्टी है, वो है जन सुराज। बाकी पार्टियां बरसाती मेंढक हैं। हर चुनाव में कुछ नई पार्टियां आती हैं और फिर वो विलुप्त हो जाती हैं। फिर अगले चुनाव में किसी और नाम से खड़ी होती हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट भी है।'

बिहार में पदयात्रा करने के बाद प्रशांत किशोर ने पिछले साल गांधी जयंती के अवसर पर आधिकारिक तौर पर जन सुराज पार्टी के गठन की घोषणा की थी। जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती कहते हैं, 'जन सुराज बदलाव की लहर है। हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि पिछले 35-40 सालों में उनके साथ जैसा बर्ताव हुआ है, वो धोखे से कम नहीं है।'

'बिहार की जनता को एक नए विकल्प की ओर देखने की जरूरत है। अगर उनको लगता है कि ये नया विकल्प जन सुराज है, तो वो जन सुराज को वोट दें। हमारा पूरा का पूरा मुहिम, हमारा पूरा अभियान, पूरी प्रक्रिया इस सोच पर आधारित है। जनता इस बात को समझ गई तो इसी बात की लहर आने वाले चुनाव में दिखेगी।'

बिहार की राजनीति में जाति फैक्टर हावी रहता है। प्रत्येक दल के अपने-अपने जातिगत समीकरण हैं। ऐसे में विकास और बदलाव की बात करने वाले प्रशांत किशोर के लिए वोटर्स को साधना एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है।

जातीय आधार पर वोटिंग के सवाल पर भारती कहते हैं, 'देश के लगभग हर राज्य में जातिगत आधार पर वोटिंग होती है। तो बिहार उससे अछूता नहीं है। ये तो कुछ राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए भ्रम फैला रखा है कि बिहार में जातिगत वोटिंग बहुत अधिक होती है। इतिहास से आप उदाहरण देखें। चाहें वह 1984 हो या फिर 1989, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। या फिर 2014 की बात हो, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त लोगों ने जाति से उठकर केवल मुद्दों के आधार पर वोटिंग की थी। एक लहर होती है, जिसपर हर किसी का ध्यान आकृष्ट हो जाता है।'

'वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद का मानना है कि जन सुराज के लिए स्थापित पार्टियों के जातिगत वोटबैंक में सेंध लगाना एक बड़ी चुनौती होगी। आरजेडी के पास 'MY' (मुस्लिम-यादव), बीजेपी के पास अपर कास्ट, नीतीश के पास महादलित और ईबीसी वोट है। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ चार पार्टियों के पास ही सभी जातियों का वोट है। कास्ट पर किसी का 100 फीसदी प्रभाव नहीं होता है। कुछ खाली जगह भी होती है। ऐसे में प्रशांत किशोर बचे हुए वोटर्स को टारगेट करेंगे।'

इस साल 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में आयोजित पान महारैली से आईपी गुप्ता सुर्खियों में आए थे। इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग जुटे। इसी कार्यक्रम में उन्होंने इंडियन इंकलाब पार्टी (आईआईपी) के गठन का भी ऐलान किया। दरअसल, गुप्ता लंबे समय से तांती-ततवा (पान) समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। आईपी गुप्ता कहते हैं, '78 सालों से हमारी कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं है। बिहार में हमारी संख्या 1 करोड़ है। अपनी आरक्षण की मांग को सड़क से सदन तक ले जाने के लिए और अपने लोगों की ताकत को संरक्षित करने के लिए मैंने इंडियन इंकलाब पार्टी का गठन किया है। वोट की चोट से आरक्षण वापसी के नारे के साथ इंकलाब पार्टी का गठन हुआ है।'

'हालांकि, वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का मानना है कि बिहार में सिर्फ एक जाति के भरोसे राजनीति करना मुश्किल है। मुझे उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं लगती है। एक जाति के आधार पर बिहार की राजनीति में बदलाव की बात करना समझ से परे है। अगर सबको साथ लेकर चलते और उसमें तांती-ततवा पूरी तरह से साथ होती तो कोई बात होती। जैसे आरजेडी का 'MY' समीकरण है, उस तरह से वो भी कोई समीकरण तैयार करते तो कुछ हो सकता था। सिर्फ तांती-ततवा के भरोसे बिहार में वे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।'

विधानसभा चुनाव से पहले 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे शिवदीप लांडे ने खाकी छोड़ खादी धारण कर ली है। इस साल अप्रैल महीने में उन्होंने हिंद सेना पार्टी के गठन का ऐलान किया। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद से ही लांडे की राजनीतिक एंट्री को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव लड़ने के सवाल पर लांडे ने कहा था कि उनकी पार्टी सौ फीसदी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि, उन्होंने ये नहीं बताया था कि वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगे।

(द क्विंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

आपसी दोस्ती, किसान नुकसान और सम्मान!

- ट्रंप टैरिफ पर पहली बार मोदी ने यूएस को दिए चार बड़े संदेश

पीएम मोदी ने कहा-किसानों-पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति और अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को परोक्ष रूप से साफ-साफ संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को दो टूक कहा कि भारत अपने किसानों और डेयरी क्षेत्र के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से इसकी भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 फीसदी करने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का यह बयान आया है। हालांकि, दोनों देश अभी भी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। यह व्यापार समझौता भारत के कृषि और डेयरी बाजार तक अधिक पहुंच की अमेरिका की मांग के बीच हो रहा है।

कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं

प्रधानमंत्री ने कहा,हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनीं, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को हरेक सुविधा पहुंचाकर, उन्हें आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है और ये भरोसा टूटने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, ''मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।'' प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अमेरिका का जिक्र तो नहीं किया लेकिन उन्होंने सांकेतिक भाषा में कह दिया कि भारत झुकने वाला नहीं है।

दोस्ती में बराबरी का हो रिश्ता,अन्यथा हर नुकसान कबूल

प्रधानमंत्री ने अपने दूर बैठे मित्र ट्रंप को दोस्ती का भी पाठ पढ़ाया है और दो टूक लहजे में कहा है कि मित्रता में बराबरी का ही रिश्ता होना चाहिए। अन्यथा वह हर नुकसान को झेलने को तैयार हैं। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर उन्होंने महान वैज्ञानिक स्वामीनाथन के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया।

सीआरपीएफ की गाड़ी फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी

- 3 की मौत, 5 गंभीर,21 जवान सवार थे,जम्मू के ऊधमपुर में हादसा

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार सुबह 10.30 बजे सीआरपीएफ जवानों की बंकर गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। प्रशासन के मुताबिक, 5 जवानों की हालत गंभीर

है। सीआरपीएफ के अफसरों के अनुसार,गाड़ी जवानों के एक दल को ले जा रहा था, जो सड़क से फिसलकर खड़ी ढलान से नीचे खाई में जा गिरा। 3 शव घटनास्थल से बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कई घायल जवानों को गंभीर हालत में रेस्क्यू कर पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधमपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक्स पर बताया,उधमपुर, कंदवा-बसंतगढ़ क्षेत्र में सीआरपीएफ के एक वाहन के दुर्घटना का शिकार होने से दुखी हूं। वाहन में सीआरपीएफ के कई बहादुर जवान सवार थे। वह हालात पर नजर रख रहे हैं।

नरसिंहगढ़ में मुख्यमंत्री ने दिया लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन का शगुन

भाई-बहन के अमिट रिश्ते का प्रतीक है रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार : सीएम

आज प्रत्येक लाड़ली बहना को 250 रुपए राखी का शगुन मिलाकर मिले 1500 रुपए

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में भाई-बहन के अमिट रिश्ते का प्रतीक है, जो सामाजिक एकता और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करता है। रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के प्रेम का पर्व नहीं, बल्कि नारी गरिमा और सामाजिक सुरक्षा का भी संदेश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हर रिश्ता परिभाषित और पूज्यनीय होता है। उन्होंने द्रौपदी और श्रीकृष्ण की रक्षाबंधन कथा का उल्लेख करते हुए इसे भाई-बहन के रिश्ते की शक्ति का प्रतीक बताया, जहाँ श्रीकृष्ण ने जीवनभर द्रौपदी की रक्षा का संकल्प निभाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिये निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख 89 हजार लाड़ली बहनों के खातों में 1,859 करोड़ रुपए अंतरित किये। साथ ही उज्जवला योजना के अंतर्गत 28 लाख से अधिक बहनों को 43.90 करोड़ सहायता राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न योजनाओं के हितलाभ वितरण भी किये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और कन्या-पूजन कर किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हजारों साल से भारतीय कुटुम्ब परंपरा में सभी रिश्तों का महत्व है।

इस बार का रक्षाबंधन ऑपरेशन सिंदूर के नाम; मंच पर बंधवाई राखी

सीएम ने कहा कि इस बार का रक्षाबंधन ऑपरेशन सिंदूर के नाम रहने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व से देश में आतंकी घटनाएं बंद हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर दुश्मन को खत्म किया है। भाई अपनी जान की परवाह किए बिना बहन के सिंदूर की रक्षा करते हैं। बहनों का सुहाग उजाड़ने वालों को सबक सिखाया। इस बार 15 अगस्त ऑपरेशन सिंदूर के नाम होगा। जब देश सुरक्षित रहेगा तो भाई-बहन का रिश्ता सुरक्षित रहेगा। दुनिया के 200 से अधिक देशों में कोई देश को माता की तरह नहीं मानता है। हम अपने देश को माता की तरह देखते हैं। इसीलिए भारत माता की जय बोलते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने लाड़ली बहनों को दी जा रही राशि 1000 से बढ़ाकर अब 1250 रुपए हो चुकी है। इसे आगे 3 हजार रुपए तक लेकर जाएंगे। राज्य सरकार ने अब तक 41 हजार करोड़ से अधिक राशि लाड़ली बहनों को बांटी है। प्रदेश में 1 करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनें हैं।

सुप्रभात

एक आदमी

कितनी भीड़ में नहीं रहेगा अकेला
और कितने अकेले में नहीं होगा निष्क्रिय
कौन कितनी बार मारा जाएगा
इस एक देह के संसार में?

ऐसे अनन्त सीधे सवालों के बीच
सभी के पास दूसरों की दया पर
टिका हुआ जीवन है
जिसमें किनारे की ज़मीन की तरह
घटनाएँ किसी विशाल नदी में धसक रही हैं

धीरे-धीरे एक मरियल-सा शहर
तबदील हो रहा है व्यायामशाला में
स्वार्थों के ध्वज मिलकर
लहरा रहे हैं शामिल पताका में

अर्थशास्त्र ने निरस्त कर दिया है
परमाणु-युद्ध

इस नये समय में
किसी भी स्वप्न के टूटने की आवाज़
नहीं जाएगी दूर तक

मुमकिन यही कि एक छोटी-सी हँसी
हमें बहुत बड़े विलाप से बचाए
और एक कोमल पाप भी
बहुत कठिन कर दे हमारा यह जीवन।

- कुमार अंबुज

इसी महीने भारत आएंगे राष्ट्रपति पुतिन

- रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद एनएसए डोभाल ने की पुष्टि
- यूक्रेन वॉर के बाद पहला भारत दौरा,अहम मानी जा रही है यात्रा

मॉस्को/नई दिल्ली (एजेंसी)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आ सकते हैं। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक, यह जानकारी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने दी है। डोभाल ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात में कहा -अब हमारे बहुत अच्छे रिश्ते बन गए हैं, जिनकी हम कदर करते हैं। हमारे देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है और हम हाई लेवल पर बातचीत करते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बुधवार को रूस पहुंचे हैं।

अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 60 पीड़ित परिवार जाएंगे यूएस कोर्ट

टॉप एविएशन वकील को किया हायर,कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मांगा

अहमदाबाद (एजेंसी)। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले मृतकों के 60 परिवारों ने बोइंग कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला किया है। इन परिवारों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की निर्माता कंपनी बोइंग के खिलाफ एक अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी विशेषज्ञ वकील माइक एंड्रयूज को भी हायर कर लिया है। इन परिवारों ने दुर्घटना की जांच पर सवाल उठाए हैं। परिवार की मांग है कि उन्हें कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का कच्चा डेटा दिया जाए, ताकि वे स्वतंत्र जांच करवा सकें। अमेरिकी वकील माइक एंड्रयूज, गंभीर चोट और अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों के विशेषज्ञ हैं। इससे पहले वे फोर्ड और वोक्सवैगन समेत कई विमान, ट्रक और कार बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ भी कई केस लड़ चुके हैं। हादसे में 270 लोगों की जान गई 12 जून को दोपहर 1.38 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान 171 (बोइंग 787 ड्रीमलाइनर) मेघाणीनगर में आईजीपी कंपाउंड में क्रैश हो गया था। विमान में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। 230 यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। हादसे में रमेश विश्वास नाम का एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया। जबकि 241 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा, डॉक्टर्स हॉस्टल अतुलयम, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, के एक इंटर्न डॉक्टर, कर्मचारी और स्थानीय लोग मारे गए। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 270 हो गई।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 35 °c

न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 8 अगस्त 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

एनडीए का फैसला

उपराष्ट्रपति कैंडीडेट मोदी-नड्डा तय करेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार को 14वां दिन था। आज भी विपक्ष के प्रदर्शन के चलते लोकसभा और राज्यसभा में पूरे दिन की कार्यवाही नहीं हो सकी। बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा व राज्यसभा को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदन में नेताओं की बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू शामिल हुए।

मीटिंग के बाद रिजिजू ने बताया कि मीटिंग में एनडीए ने प्रस्तावना पास करते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंडीडेट का नाम तय करने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को सौंपा है। इधर, लोकसभा में आज नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) बिल, 2025 को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने पर फैसला नहीं हो सका। विपक्ष ने दोनों बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग की है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह को लेटर लिखकर बिहार एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग की थी। हालांकि,एसआईआर पर चर्चा को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा का नियम है कि कोर्ट में लंबित मामलों पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इसके अलावा दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मीटिंग भी हुई है।

कबूतरों को दाना डालने पर मुंबई में नया बवाल

सड़क पर उतरा गुजराती-जैन समुदाय, सीएम को देना पड़ा दखल

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई में मराठी-गैर मराठी विवाद के बाद अब एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। बीएमसी चुनावों से पहले उठा यह विवाद अब सियासी रंग लेने लगा है और धीरे-धीरे स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई का मुद्दा बनता जा रहा है। दरअसल, कबूतरों को दाना डालने की वजह से स्थानीय और बाहरी यानी जैन और गुजराती समुदाय के बीच तनातनी बढ़ गई है। स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जैन और गुजराती समुदाय के सदस्यों ने

कथित तौर पर दादर कबूतरखाने के ऊपर से तिरपाल फाड़कर कबूतरों को दाना क्यों डाला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद कबूतरखाने के ऊपर तिरपाल डाल दिया गया था। जैन समुदाय और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस प्रतिबंध का विरोध किया है और कहा है कि कबूतरों को दाना डालने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए,अन्यथा पक्षी भूखे मर जाएंगे। इसी कड़ी में सड़कों पर उतरे जैन और गुजराती समुदाय के लोगों ने तिरपाल फाड़कर दाना डाल दिया।

मुख्यमंत्री आज तामोट में 1132 करोड़ रुपए के निवेश कार्यों एवं 416 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात

औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन/लोकार्पण कर वितरित करेंगे आशय पत्र

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव औद्योगिक विकास को धरातल पर उतारने के अपने सतत प्रयासों के क्रम में 8 अगस्त को रायसेन जिले के तामोट औद्योगिक क्षेत्र में निवेश संवाद, इकाइयों के भूमिपूजन, लोकार्पण और आशय पत्र वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा उद्योगों को लेकर उनकी प्रतिबद्धता और कार्य संस्कृति का प्रतिबिंब है, जिसमें नीति के साथ क्रियान्वयन को भी बराबरी का महत्व दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव तामोट में संचालित सागर मैन्युफैक्चरर प्रा. लि. की इकाई का भ्रमण करेंगे और रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव मेसर्स आनंद टैक लास्ट प्राइवेट लिमिटेड प्लास्टिक पार्क का भ्रमण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव उद्योगपतियों से संवाद करेंगे और प्रदेश में बन रहे निवेश अनुकूल वातावरण से उन्हें अवगत कराएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव औद्योगिक क्षेत्र तामोट में 566 करोड़ रुपए के निवेश एवं 1781 रोजगार देने वाली 14 इकाइयों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण के साथ आशय पत्र वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 416 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव औद्योगिक क्षेत्र तामोट में 300 करोड़ निवेश एवं 970 रोजगार देने वाली 6 इकाइयों का भूमिपूजन और 116 करोड़ रुपए से अधिक निवेश एवं 211 रोजगार देने वाली 6 इकाइयों का लोकार्पण करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव उद्यमियों को भूमि आवंटन से संबंधित आशय-पत्र प्रदान करेंगे और औद्योगिक विकास के प्रति प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं को साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का यह प्रयास निवेशकों को आश्वस्त करने के साथ-साथ युवाओं के लिए नए रोजगार अवसरों का रास्ता भी खोलेगा।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन तथा एमएसएमई प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह प्रदेश की औद्योगिक रणनीति और नीतिगत परिवर्तनों की जानकारी साझा करेंगे। जे.बी.एम, विनप्रो और मंडीदीप औद्योगिक एसोसिएशन जैसे प्रमुख निवेशक समूहों के प्रतिनिधि मध्यप्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल और प्रदेश की निवेश फ्रेंडली नीतियों के संबंध में विचार साझा करेंगे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, भोजपुर विधायक श्री सुरेंद्र पटवा और विधायक श्री नारायण सिंह पंवार भी कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे।

एम्स भोपाल के डॉ. स्नेहिल गुप्ता वर्ल्ड साइकियाट्री एसोसिएशन की साइकेट्री एजुकेशन समिति के सदस्य निर्वाचित

भोपाल। एम्स भोपाल निरंतर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। इसी क्रम में संस्थान के मनोरोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. स्नेहिल गुप्ता को वर्ल्ड साइकियाट्री एसोसिएशन की साइकेट्री एजुकेशन सेक्शन की समिति में सदस्य के रूप में चुना गया है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत यह संस्था वैश्विक स्तर पर सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित संगठनों में से एक मानी जाती है। डॉ. गुप्ता का यह कार्यकाल वर्ष 2025 से 2028 तक रहेगा, जिसमें वे समिति के अन्य अंतरराष्ट्रीय सदस्यों के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर मनोरोग शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। उनके प्रयासों का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली मनोरोग शिक्षा में व्याप्त असमानताओं को कम करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, साइकेट्री ट्रेनी एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करना और नीति निर्माताओं व प्रमुख हितधारकों के साथ मिलकर मनोरोग शिक्षा एवं व्यावसायिक मानकों को सशक्त बनाना रहेगा। यह उपलब्धि न केवल डॉ. स्नेहिल गुप्ता की अकादमिक व नैदानिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, बल्कि एम्स भोपाल को वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य पहलों में एक अहम भागीदार के रूप में भी प्रस्तुत करती है।

राज्यपाल ने प्रो. मिश्र को महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलगुरू नियुक्त किया

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगुभाई पटेल ने प्रो. शिव शंकर मिश्र को महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का कुलगुरू नियुक्त किया है। प्रो. मिश्र वर्तमान में श्री लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं। श्री मिश्र को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 04 वर्ष की कालावधि के लिए कुलगुरू नियुक्त किया गया है। जारी आदेश के अनुसार इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगे।

जनहित के सवालों से भागती रही सरकार, विपक्ष ने उठाई जनता की आवाज़: उमंग सिंघार

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की समाप्ति के बाद आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भोपाल में मीडिया से चर्चा की और सरकार को जनहित के मुद्दों पर जवाबदेही से बचने के लिए कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सरकार की नीयत साफ़ तौर पर जनविरोधी रही और वह लगातार चर्चा से भागती रही।

ओबीसी आरक्षण पर सरकार भाग रही है चर्चा से - नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने बार-बार सदन में ओबीसी आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार चर्चा से भागती रही। यह मुद्दा सामाजिक न्याय से जुड़ा है, सरकार की चुप्पी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

आदिवासियों के मुद्दों से भी बच रही है सरकार - सरकार आदिवासी अधिकारों, वनाधिकार और जमीन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा से बचना चाहती है।

हमारा संघर्ष जारी रहेगा — हम अपने मुद्दों पर अडिग हैं। सरकार ने आधुनिक तकनीक की हमारी बात पर आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि आदिवासियों को उनका हक मिलेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ प्रभावशाली लोग वन अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध जंगल कटवा रहे हैं। यह आदिवासियों के जीवन, पर्यावरण और जंगल की आत्मा पर हमला है।

युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे- नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनसेवा मित्र, संविदा शिक्षक और अतिथि कर्मचारियों को नियमित नहीं करना चाहती सरकार। प्रदेश के युवाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है।

श्रमिकों के अधिकारों का हनन - नए श्रम कानूनों के तहत मज़दूरों का हक छीना जा रहा है। हड़ताल से कई दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे तत्काल मुद्दों पर विरोध असंभव हो गया है।

महानगर विधेयक पर सरकार की चुप्पी - उमंग सिंघार ने कहा कि जबलपुर, ग्वालियर और रीवा को मेट्रोपोलिटन घोषित करने पर न कोई विधेयक आया, न चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर को महानगर बनाए जाने से लाखों हेक्टेयर जमीन जाएगी – क्या किसानों को बाज़ार मूल्य पर मुआवज़ा मिलेगा?

किसानों को खाद की किल्लत - नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश के किसान खाद के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है। मुख्यमंत्री और मंत्री वास्तविकता से कटे हुए हैं, ज़मीन पर जाकर किसानों से मिलना जरूरी है। तब सच्चाई पता चलेगी।

स्टाम्प ड्यूटी में भारी वृद्धि - सरकार ने 100 प्रतिशत से 400 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क बढ़ाकर आम जनता पर महंगाई का बोझ डाला है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम कर्ज ले रहे हैं दूसरी तरफ जनता पर मंहगाई का बोझ डाल रही है।

कानून व्यवस्था - नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई है लेकिन मुख्यमंत्री गृह विभाग का मोह छोड़ने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि झूठे मुक़दमे दर्ज कर पुलिस राज चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा चंबल में 'डकैती अधिनियम' समाप्त किया जाए। इसके साथ ही विधायकों पर भी फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने की बात भी नेता प्रतिपक्ष ने कही।

पूरे सत्र में सरकार सवालों से भागती रही - उन्होंने कहा कि अधिकतर सवालों पर मंत्रियों के जवाब थे - जानकारी एकत्र की जा रही है। जब विपक्ष जनता की बात उठा रहा था, मुख्यमंत्री मौन या अनुपस्थित रहे।

महाराष्ट्र में 'खेला', 40 लाख वोटर हैं रहस्यमय!

● राहुल गांधी का बड़ा आरोप,ईसी और बीजेपी को घेरा

राहुल ने कहा-महाराष्ट्र-हरियाणा में हुई है फर्जी वोटिंग

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के एसआईआर प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने वोटर लिस्ट को लेकर इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वोटिंग पर लोगों को शंका हो रही। अब चुनाव प्रक्रिया लंबे समय तक चल रही है। यूपी में अलग दिन और बिहार अलग दिन मतदान होता है। महीनों चलने वाली चुनाव प्रक्रिया के बाद एग्जिट पोल में कुछ और नतीजे नजर आते हैं और रिजल्ट दूसरा आता है। महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 40 लाख वोटर रहस्यमय हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता-विरोधी भावना एक ऐसी चीज है जो हर लोकतंत्र में हर पार्टी को प्रभावित करती है लेकिन किसी कारण से, बीजेपी लोकतांत्रिक ढांचे में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मूल रूप से सत्ता-विरोधी भावना से ग्रस्त नहीं है। अचानक परिणाम बड़े पैमाने पर बदलाव के साथ पूरी तरह से अलग दिशा में चले जाते हैं।

ईसी ने कहा-साइन करें या फर्जी आरोप ना लगाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगातार हमले जारी हैं। वह महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा इलेक्शन में धांधली के आरोप लगा चुके हैं। ताजा मामला कर्नाटक का है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक में एक लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और इस तरह वोटों की चोरी हुई है। अब इस मामले में राहुल गांधी को कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने एफिडेविट भेजा है। उन्होंने राहुल गांधी से मांग की है कि इस हलफनामे पर साइन कर दें कि वह सही आरोप लगा रहे हैं। यदि उनके दावे गलत पाए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व मंत्री मजीठिया की जमानत पर नहीं हो पाया फैसला

● मोहाली कोर्ट में 2 घंटे तक चली सुनवाई, विजिलेंस ने कहा-यूपी तक की जांच

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब के पूर्व मंत्री व शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर मोहाली कोर्ट में करीब दो घंटे तक सुनवाई हुई। दोनों तरफ के वकीलों की लंबी बहस चली। लेकिन इस मामले कोई फैसला नहीं हो पाया है। कोर्ट ने मामले की कल फिर से सुनवाई करने का फैसला लिया है। मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 25 जून को अमृतसर स्थित घर से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे न्यू नाभा जेल में बंद हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर कई दिनों से सुनवाई चल रही है। आज 7वीं बार सुनवाई हुई है। दोनों तरफ से लंबी दलीलें पेश की गईं। विजिलेंस का कहना है कि हमारी टीमें हिमाचल व उत्तर प्रदेश तक जाकर आई हैं। कई तथ्य हमारे पास हैं। हालांकि मजीठिया के वकीलों का अलग ही कहना था।

राजगढ़ में सीएम यादव ने किया रोड शो

राजगढ़ (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लाड़ली बहनों से राखी बंधवाने राजगढ़ के नरसिंहगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्य सड़क से रोड शो किया। मुख्यमंत्री यहां आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख बहनों के खातों में कुल 1 हजार 859 करोड़ रुपए का अंतरण की।

अर्जुन तिराहा से बस स्टैंड तक रोड शो हुआ- मुख्य कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने नरसिंहगढ़ में रोड शो किया। यह शो अर्जुन तिराहा से बस स्टैंड तक निकला। इस दौरान अलग-अलग समाजसेवी संगठनों ने उनका स्वागत किया।

हाईवे की हालत खराब, फिर किस बात का 'टोल टैक्स'

केरल हाईकोर्ट ने एनएचएआई को दिखाया आईना,जमकर फटकारा

तिरुअनंतपुरम (एजेंसी)। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाते हुए एक नेशनल हाईवे पर चार हफ्तों के लिए टोल टैक्स वसूलने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एडापल्ली से मन्नुथी जाने वाले नेशनल हाईवे-544 की खराब हालत के बाद भी वसूले जा रहे टोल टैक्स को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। कोर्ट के मुताबिक जब पूरे रोड की हालत खराब है और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है तो फिर वह जनता से किस बात का टोल वसूल कर रहे हैं। जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन की बेंच ने इस मामले में एनएचएआई को भी जमकर लताड़ लगाई। कोर्ट ने कहा कि एनएचएआई और उसके एजेंट्स की यह जिम्मेदारी है कि वह जनता के लिए सुरक्षित और आसान जगह बनाएँ। अगर किसी कारण से यह संभव नहीं है, तो फिर टोल टैक्स वसूलना कानूनी रूप से गलत है। कोर्ट ने कहा कि जनता और सरकार के बीच में एक भरोसे का रिश्ता होता है, जब सरकार उस भरोसे पर खरा नहीं उतर पा रही है तो वह जनता के ऊपर जबरदस्ती टैक्स नहीं थोप सकती। इतना ही नहीं कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या समझौता आम जनता के हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है।

अब दूर देश कनाडा में भगवान राम की जय-जयकार

● उत्तरी अमेरिका के इस शहर में लगी 51 फीट ऊंची प्रतिमा ● भारतीयों के लिए गर्व की बात, बन गया है खास लैंडमार्क

ओटावा (एजेंसी)। भारत से बाहर अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जहां भगवान राम की जय-जयकार के साथ शहर भर में गूंज हो गई, हर तरफ भीड़ ही भीड़ और लोग बस हाथ जोड़े या हाथ में राम जी की तस्वीर का झंडा लिए खड़े थे। हम बात कर रहे हैं उत्तर अमेरिका के कनाडा देश के मिसिसॉगा शहर की, जहां दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ती का उद्घाटन हुआ। यह मूर्ति 51 फीट ऊंची है और पूरे उत्तर अमेरिका में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जा रही है। इसे शहर के हिंदू हेरीटेज सेन्टर में स्थापित किया गया है। इस मूर्ति के अलग-अलग हिस्सों को दिल्ली शहर में बनवाया गया था और बाद में कनाडा में जोड़ दिया गया था। इसका स्टील का ढांचा इस तरह से बना है कि ये 100 साल तक टिक सकता है और 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं को भी सहन कर सकता है। ये मूर्ति अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर से प्रेरित होकर बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 4 साल पहले की गई थी और इसे पूरा करने के लिए इंडो-कैनेडियन (भारतीय मूल के कनाडाई) बिजनेसमैन ने फंडिंग की थी। खास बात तो ये है ये मूर्ती ऐसी जगह लगी है, कि जब कोई हवाई जहाज टोरंटो के पियरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है, तो ऊपर से ये मूर्ति साफ दिखाई देती है। प्रतिमा के बारे में कहा जा रहा है, इसके सही सलामत रहने की उम्मीद कम से कम 100 साल है। हिन्दू हेरिटेज सेंटर के फाउंडर आचार्य सुरिंदर शर्मा शास्त्री का कहना है, ये प्रतिमा कम्युनिटी के लिए स्पेशल गिफ्ट है। ये मूर्ति आपसी सांस्कृतिक एकता, शांति और विरासत का प्रतीक है, जिसे हर भक्त के लिए समर्पित किया गया है। ये भव्य प्रतिमा हिंदू संस्कृति की झलक दिखाती है और ये उपलब्धि उत्तर अमेरिका में बसे भारतीयों के लिए गर्व का एक खास पल बन गई है। टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित होने की वजह से यह मूर्ति अब आने वाले यात्रियों को दिखने वाले पहले प्रमुख स्थलों में से एक बन गई है। बता दें, यह मूर्ति मिसिसॉगा के हिंदू हेरिटेज सेंटर के परिसर में लगाई गई है।

सिंहस्थ के पहले शिप्रा घाट बनाने सरकार लगाएगी केविएट

नदी के दोनों ओर बनेंगे 29 किमी लंबे घाट ,निर्माण न रोकना पड़े इसलिए उठाया कदम

भोपाल (नप्र)। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में जुटी मोहन यादव सरकार शिप्रा के दोनों ओर बनाए जाने वाले 29 किमी लंबे घाट का काम शुरू कराने के बाद इसे तेजी से पूरा कराएगी। सरकार को आशंका है कि घाट निर्माण के दौरान विरोध हो सकता है, इसे देखते हुए सरकार जल संसाधन विभाग के जरिये हाईकोर्ट में केविएट दायर करने की तैयारी कर रही है, ताकि निर्माण के विरोध में कोर्ट जाने वालों के आवेदन पर कोर्ट एकतरफा फैसला न दे।

इसको लेकर जल संसाधन विभाग ने नमामि शिप्रे परियोजना क्रियान्वयन इकाई उज्जैन को पत्र लिखकर कहा है कि सिंहस्थ महापर्व 2028 के लिए शिप्रा नदी के दाएं और बाएं तट पर 29.215 किमी घाट का निर्माण किया जाना है। 778.91 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे घाट को लेकर 31 दिसम्बर 2024 पत्र लिखा गया था।

जल संसाधन विभाग के वृहद परियोजना मंडल ने इन घाटों के निर्माण को लेकर 8 मई 2025 को स्कोप ऑफ वर्क के अंतर्गत टेंडर मंजूर कर दिया है। सरकार को आशंका है कि इस काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है और निर्माण कार्य के विरोध में कुछ लोग कोर्ट जा सकते हैं।

इंदौर हाईकोर्ट में दायर होगी केविएट- शिप्रा नदी के किनारे सरकार बिना किसी विवाद के निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में केविएट दायर करने जा रही है ताकि अगर कोई इसमें बाधा की स्थिति पैदा करना चाहे और कोर्ट जाए तो इसकी जानकारी परियोजना प्रशासक नमामि शिप्रे परियोजना क्रियान्वयन इकाई-2 जल संसाधन विभाग उज्जैन को मिले और विभाग तथा सरकार की ओर से इस पर जवाब दिया सके। ताकि कोर्ट सरकार का पक्ष सुनकर ही फैसला दे।

घाटों पर लगेंगे रामघाट जैसे रेड स्टोन- कान्ह और शिप्रा नदी पर बनाए जाने वाले घाटों पर पहले स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्टोन लगाकर घाट तैयार करने का निर्णय हुआ था, लेकिन बाद में यह तय किया है कि रामघाट के जैसे रेड स्टोन से घाट बनाए जाएंगे। इसलिए इसकी डीपीआर की शर्तों में बदलाव किया है। अन्य काम भी समय पर पूरे करने की तैयारी विभाग ने की है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रामघाट जैसे स्टोन का इस्तेमाल पूरे 29 किमी के घाट निर्माण में किया जाएगा।

यहां भी होना है निर्माण

- गोठड़ा से शनि मंदिर तक कान्ह नदी के दोनों तटों पर घाट निर्माण
- शिप्रा नदी के बाएं और दाएं तट पर शनि मंदिर से नागदा बायपास तक घाट निर्माण
- आत्मोलिंगेश्वर मंदिर के पास
- भर्तृहरि गुफा के पास
- अंगारेश्वर मंदिर के पास वेंटेड कॉजवे का निर्माण कार्य
- कान्ह नदी पर पंथपिपलाई, जमालपुरा, गोठड़ा, स्टाप डैम
- पिपलिया राघौ बैराज नंबर 2
- रामवासा बैराज नंबर 2 का स्टाप डैम का निर्माण कार्य
- शिप्रा नदी पर किथोदाराव बैराज का निर्माण
- उंडासा और जस्ताखेड़ी तालाब का मरम्मत कार्य
- दुर्गादास की छतरी के पास सीसी रोड निर्माण कार्य

प्रदीप मिश्रा की कथा से लौट रहे श्रद्धालुओं का एक्सीडेंट, तेज रफ्तार तूफान गाड़ी ट्रक में जा घुसी ; 1 की मौत, 14 घायल

भोपाल (नप्र)। गुरुवार अलसुबह इंदौर के कनाड़िया बायपास पर एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि लगभग 14 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस

से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह करीब 4 बजे बिचौली मर्दाना ब्रिज के पास हुआ। यहां एक तेज रफ्तार तूफान वाहन अचानक सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में मंटू वर्मा, निवासी इंदिरा नगर, खरगोन की मौके पर ही मौत हो गई। मंटू, मुन्नालाल वर्मा का पुत्र था और फर्स्ट ईयर का छात्र था। वह पढ़ाई के साथ-साथ पिता के सब्जी व्यवसाय में भी मदद करता था। परिवार में उसकी एक बहन भी है।

आरजीपीवी में हुई मारपीट ,2 छात्र 6 माह के लिए निलंबित

6 स्टूडेंट्स को हॉस्टल से किया बाहर; अभिभावकों से लिए जाएंगे एफिडेविट

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) में छात्रावास में हुई मारपीट और रैगिंग के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। यूजीसी एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन को दर्ज शिकायत और जांच के बाद कुल 8 छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

2 अगस्त की रात करीब 10 बजे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (यूआईटी) के बाल्टिक हॉस्टल और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर (एसओए) हॉस्टल के छात्रों में कहासुनी मारपीट तक पहुंच गई। विवाद की शुरुआत एक फोन कॉल पर हुई थी। आरोप है कि फोन पर बात करने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों हॉस्टलों के छात्र डंडे और लोहे की रॉड लेकर आमने-सामने आ गए। इस झगड़े में कई छात्र घायल हुए, हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिससे मामला और गंभीर हो गया। 3 अगस्त को यह शिकायत यूजीसी एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन को मिली, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। 5 और 6 अगस्त को एंटी-रैगिंग समिति की बैठक हुई। समिति ने दोषी छात्रों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की।

6 छात्रों को हॉस्टल से निकाला गया

6 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि इन्हें चेतावनी पत्र जारी किया जाए और अभिभावकों से शपथ-पत्र (एफिडेविट) लिया जाए कि छात्र भविष्य में अनुशासनहीनता में शामिल नहीं होंगे। शपथ-पत्र जमा करने के बाद ही इन छात्रों को नवंबर-दिसंबर 2025 की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

प्रशासन का सख्त संदेश

आरजीपीवी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की रैगिंग, हिंसा या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर भविष्य में और कड़ी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही हॉस्टल में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल से रीवा के लिए स्पेशल रक्षाबंधन ट्रेन

आरकेएमपी से 8 अगस्त की शाम को चलेगी; 9 को रीवा से आएगी

भोपाल (नप्र)। भोपाल से रीवा के बीच रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन चलेगी। 8 अगस्त की शाम को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से यह रैक रवाना होगा। वहीं, 9 अगस्त की सुबह रीवा से भोपाल के लिए लौटेगी। यात्रियों की सुविधा और बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने रानी कमलापति-रीवा-रानी कमलापति के मध्य एक-एक ट्रीप की एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

पं. सुंदरलाल श्रीधर स्मृति राज्य स्तरीय निबंध स्पर्द्धा

भोपाल। अग्रिम पंक्ति के स्वंतत्रता सेनानी, भूदान यज्ञ आंदोलन के प्रमुख स्तम्भ रहे तपोनिष्ठ पं. सुंदरलाल श्रीधर (1919-2000) गौरव मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष भी राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता के लिए 15 से 29 वर्ष आयु समूह के युवाओं से प्रविष्टियां आमंत्रित हैं। विषय है: 'स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की

ओर बढ़ता देशः वर्तमान परिदृश्य, अपेक्षित प्राथमिकताएं।' निबंध अधिकतम 1500 शब्दों का हो। सुवाच्य अक्षरों में 4 साइज के पेपर पर लिखा अथवा टाइप किया हुआ निबंध 10 सितंबर 2025 तक माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय, मेन रोड नंबर 3, भोपाल (म.प्र) 462003 के पते पर पहुंच जाना चाहिए। प्रतिभागी इस बात का ध्यान रखें कि उनके द्वारा प्रेषित निबंध मे व्यक्तिगत-राजनीतिक अथवा विवादास्पद मुद्दों पर टीका टिप्पणी ना हो। श्रेष्ठ प्रविष्टियों को प्रथम पुरस्कार 4000 रू. द्वितीय पुरस्कार 2500 रू. एवं तृतीय पुरस्कार 1500 रू. दिया जाएगा। पुरस्कार के लिए चयनित विजेताओं की घोषणा पं. सुंदरलाल श्रीधर जन्म जयंती 21 सितंबर 2025 को भोपाल में की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरसिंहगढ़ में लाड़ली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कन्या-पूजन किया।

भोपाल बन रहा देश का टैक हब, युवाओं के कॅरियर को मिलेगी नई उड़ान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल अब नवाचार का केंद्र बनकर भारत के डिजिटल भविष्य को आकार देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। यहां ड्रोन, एवीजीसी-एक्सआर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों के अग्रणी केंद्र और उद्योग साझेदारियां आकार ले रही हैं। भोपाल जल्द ही ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी हब बनेगा। एनीमेशन ग्राफ़िक्स जैसे नए सेक्टर्स भी प्रदेश के युवाओं के कॅरियर को नई उड़ान देने तैयार हैं। भोपाल में सेमी-कंडक्टर और डाटा-सेंटर जैसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स भी विकसित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की विकासमूलक रणनीतिक सोच से भोपाल का हाई-टैक इंडस्ट्रीज के लिए एक मनपसंद गंतव्य के रूप में उभरना कोई संयोग नहीं है, बल्कि, योजनाबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर एवं ईको सिस्टम का विकास और भविष्योन्मुखी नीतियों के निर्माण का परिणाम है। देशी-विदेशी कंपनियां मध्यप्रदेश में उद्यमिता को चुन रही हैं। उन्हें प्रदेश में ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस और नीतिगत प्रक्रिया सहयोग भी मिल रहा है। सेमी-कंडक्टर और ड्रोन जैसे डीप-टैक उपक्रमों से लेकर एवीजीसी और डाटा सेंटर्स तक के लिये मध्यप्रदेश भारत के डिजिटल भविष्य का लॉन्चपैड बनता जा रहा है।

एवीजीसी-एक्सआर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: ग्लोबल स्किल्स पार्क में नया क्रिएटिव हब- ग्लोबल स्किल्स पार्क, भोपाल में स्थापित हो रहा एवीजीसी-एक्सआर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस युवाओं को गेमिंग, एनीमेशन और वीएफएक्स के क्षेत्र में प्रशिक्षण और स्टार्ट-अप्स के लिए मंच देगा। इसमें एलईडी वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो, एआई लैब्स, मोशन कैप्चर सिस्टम और रेंडर फार्म्स जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। यह केंद्र देश के मेट्रो शहरों पर निर्भरता को कम करते हुए एक नया डिजिटल वर्कफोर्स तैयार करेगा।

आइसर का ड्रोन ट्रेनिंग और शोध केन्द्र बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस- आईसर भोपाल में बन रहा ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई-एनेबल्ड ड्रोन निर्माण, स्वदेशी प्रोटोटाइपिंग और एआर/वीआर आधारित प्रशिक्षण के अनूठे मंच के रूप में विकसित हो रहा है। यहां देश की पहली एआई-यूएवी डाटा रिपॉजिटरी भी स्थापित होगी, जो कृषि, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों के लिए नवाचारों को प्रेरित करेगी।

सेमीकंडक्टर निर्माण की कायनेस सेमिकॉन की इकाई भोपाल में

भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का अहम भागीदार कायनेस सेमिकॉन अब भोपाल के आईटी पार्क में अपनी इकाई स्थापित कर रहा है। इससे चिप डिज़ाइन, असेंबली और अनुसंधान को एक नई दिशा मिलेगी। यह कदम प्रदेश की डीप-टैक नीति को सशक्त करेगा।

भोपाल में बनेगा मध्यप्रदेश का पहला निजी ग्रीन डाटा सेंटर

एशिया का सबसे बड़ा रेटेड-4 हाइपरस्केल डाटा सेंटर ऑपरेटर, भोपाल के आईटी पार्क में ग्रीन डाटा सेंटर स्थापित कर रहा है। इमर्सिव कूलिंग जैसी तकनीकों से युक्त यह डाटा सेंटर जीरो-एमिशन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। यह क्लाउड और एआई कम्प्यूटिंग के क्षेत्र में प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

ईएमसी 2.0 : 209 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

भोपाल के बांदाखेड़ी में 209 एकड़ में फैला ईएमसी 2.0 क्लस्टर मोबाइल, सेमीकंडक्टर, पीसीबी, एलईडी और ई-मोबिलिटी उद्योगों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें रेडी-बिल्ट फैक्ट्री, टेस्टिंग लैब्स और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। इसमें 1500 करोड़ रूपये का निवेश होगा और इससे 75 हजार रोजगार सृजित होंगे।

सिक्योर सर्किट : पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग से आत्मनिर्भरता की ओर

भोपाल में स्थापित हो रही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) निर्माण इकाई राज्य के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करेगी। यह रक्षा, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम होगा। राज्य सरकार उद्योगों को न केवल कम समय में मंजूरी और समाधान उपलब्ध करा रही है,बल्कि निवेशकों में दीर्घकालिक साझेदारी का भरोसा भी जगाने में सफल हो रही है।

जिस महिला पर गर्म तेल डाला उसकी मौत

पुलिसकर्मियों ने अस्पताल नहीं पहुंचाया था, परिजन मिन्नतें करते रहे; चक्काजाम किया

भोपाल (नप्र)। भोपाल में तीन युवकों ने एक महिला पर गर्म तेल डाल दिया, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गई। हमीदिया अस्पताल में चार दिन चले इलाज के बाद गुरुवार (7 अगस्त) सुबह उसकी मौत हो गई। घटना रविवार रात (3 अगस्त) को अन्ना नगर की है। महिला के बेटे का आरोप है कि आरोपी मुझे मारने आए थे। मां बचाने आई तो उन्हें पीटा और गर्म तेल डाल दिया। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पीछे चाय नाश्ते की दुकान के बाहर अतिक्रमण किए जाने के विवाद बताया जा रहा है। मृतका कांति प्रजापति (35) के पति ने गोविंदपुरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को अन्नानगर इलाके में परिजन ने चक्काजाम कर दिया।

बेटे को पीटने आए थे, पत्नी बचाने पहुंची तो गर्म तेल डाला

कांति प्रजापति के पति मुकेश ने बताया कि रिश्तेदार कमलेश प्रजापति और उसका भांजा अतिक्रमण विवाद में बेटे को पीटने आए थे। यह देखकर कांति बेटे को बचाने पहुंची। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। अपनी दुकान में कड़ाही में रखे गर्म तेल को पत्नी पर उड़ेल दिया। जिसने तेल डाला वह भी झुलस गया। हमने तत्काल पुलिस को सूचना दी। गोविंदपुरा थाने की एफआरवी मौके पर पहुंची। घायल पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए निकले। रास्ते में पुलिसवालों ने आरोपियों के संबंध में पूछताछ की।

टीआई बोले- पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, आरोप निराधार

गोविंदपुरा टीआई अवधेश सिंह तोमर के मुताबिक घटना की सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। घायल महिला को करियर कॉलेज के करीब एक अस्पताल में भर्ती कराया। परिजन इस अस्पताल में भर्ती कराए जाने से संतुष्ट नहीं थे। बाद में वह खुद महिला को अपने साथ ले गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एफआईआर दर्ज की और घटना के चंद घंटे के भीतर ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी की। पुलिस पर लगे तमाम आरोप निराधार हैं।

पति बोला- एफआरवी से उतारा, एक्टिवा से अस्पताल पहुंचाया

पूछताछ के दौरान तड़पती पत्नी को करियर कॉलेज के पास उतार दिया। कहा कि यहां से खुद अस्पताल ले जाओ। वहां तक छोड़ना हमारा काम नहीं है। हम मिन्नतें करते रहे। पुलिसकर्मी नहीं माने, एक राहगीर की एक्टिवा से किसी तरह पत्नी को जेपी अस्पताल पहुंचाया। यहां से पत्नी को हमीदिया रेफर किया गया। इलाज के दौरान पत्नी की हमीदिया अस्पताल में मौत हो गई। मुकेश के मुताबिक उनकी पत्नी की मौत हो गई, बेटे को भी आरोपियों ने पीटा। इसके बाद भी उनके और उनके बेटों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। जबकि जिसने उन पर एफआईआर कराई, उसी ने पत्नी को जलाया है। यही तेल उस पर गिरा, जिससे वह झुलस गया है।

परिजन बोले- पुलिसवाले बयान लेने भी अस्पताल देर से आए

मृतका के बेटे ने बताया कि मां को एफआरवी से उतारा गया। मित्रतों के बाद भी उसमें सवार पुलिसकर्मी मां को अस्पताल पहुंचाने को तैयार नहीं हुए। इस बात को लेकर हमारी उनसे बहस हुई पर वे नहीं रुके और चले गए। पुलिस बयान दर्ज करने भी अस्पताल देरी से आई, वहां भी पुलिसकर्मी बहस करता रहा।

न्यायिक-गैर न्यायिक विभाजन से नाराज, जमा कराई गाड़ियां

भोपाल में व्यवस्था से दूसरे दिन भी नाराज राजस्व अधिकारी; काम से बनाई दूरी

भोपाल (नप्र)। राजस्व अधिकारियों के न्यायिक और गैर न्यायिक विभाजन को लेकर गुरुवार को भी विरोध हो रहा है। भोपाल के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार कलेक्टोरेट पहुंचे और अपनी गाड़ियां जमा करा दी।

भोपाल में बैरागढ़, कोलार, एमपी नगर, शहर वृत्त, बैरसिया और टीटी नगर तहसीलें हैं। इनके तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य में विभाजित किया गया है। यानी, जो अधिकारी न्यायिक कार्य कर रहे हैं, वे फिल्ड में नहीं है।

वहीं, फिल्ड वाले अधिकारी न्यायिक कार्य नहीं कर रहे। इस व्यवस्था का वे भी विरोध कर रहे हैं। बुधवार को कोर्ट समेत अन्य काम उन्होंने नहीं किए थे। गुरुवार को भी ऐसी ही स्थिति है। इस वजह से आमजनों के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो रही तो जनता से जुड़े काम भी अटक रहे हैं।

कलेक्टोरेट में एकसाथ दी चाबियां- गुरुवार सुबह सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार एकसाथ कलेक्टोरेट पहुंचे। इसके बाद उन्होंने गाड़ियों की चाबियां

सौंप दी। भोपाल में गुरुवार को सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने गाड़ियां भी सौंप दी।

मंत्री-अफसरों को सुना चुके बात- इस संबंध में मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ राजस्व मंत्री वर्मा और सीनियर अधिकारियों के सामने अपनी बात रख चुका है। इस दौरान बताया गया था कि अगले 3 महीने के लिए 12 जिलों में ही पायलेट प्रोजेक्ट के तहत यह व्यवस्था लागू की जाएगी, लेकिन बाद में 9 और जिलों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई।

इसके चलते संघ के सभी जिला अध्यक्ष, प्रभारी और प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें 6 अगस्त से विरोध करने का फिर से निर्णय लिया गया। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीनचंद कुंभकार ने बताया कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के कई जिलों में राजस्व अधिकारी विरोध कर रहे हैं।

अभी हड़ताल पर नहीं जाएंगे

विभाजन को लेकर संघ की बैठक हो चुकी है। इसमें संवर्ग में विभाजन की इस योजना के पूर्ण रूप से वापस नहीं होने तक सभी राजस्व अधिकारी आपदा प्रबंधन कार्यों को छोड़कर समस्त कार्यों से विरत रहते हुए जिला मुख्यालयों पर उपस्थित रहने का निर्णय लिया गया। हालांकि, कोई भी सामूहिक अवकाश या हड़ताल पर नहीं है। सभी राजस्व अधिकारी जिला मुख्यालय पर ही उपस्थित हैं।

एक दिन पहले बोले थे मंत्री-दिक्कतें आ रही थीं

विरोध के चलते बुधवार को ही राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा था कि यह कैबिनेट का निर्णय है। प्रोटोकॉल और न्यायालयीन प्रक्रिया में पहले बड़ी दिक्कतें आ रही थीं। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के लिए व्यवस्था नहीं की है। कुछ के लिए ही है।

संपादकीय

भारत ट्रंप के आगे न झुके!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपनी खुन्नस में भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। ट्रंप ने 25 फीसदी टैरिफ तो पहले ही लगा दिया था, जो 7 जुलाई से लागू होना था। अब जो नया 25 टैरिफ लगाया गया है, उसे लागू करने की 21 दिनों की मोहलत दी गई है। ट्रंप ने यह धमकी भी दी है कि अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई तो टैरिफ और बढ़ाया जा सकता है। भारत में अमेरिका की इस दादागिरी के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि चाहे मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन ट्रंप की दादागिरी के आगे भारत नहीं झुकेगा। पीएम ने जो कहा है, उसका लब्बोलुआब यही है कि कि उनके लिए व्यक्तिगत रिश्ते राष्ट्रहित के आगे कोई मायने नहीं रखते और ऐसे संबंध वह कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अमेरिका के इस रवैये को विश्वासघाती और निंदनीय बताया है। ट्रंप की परेशानी यह है कि उन्होंने दुनिया के सभी देशों पर मनमाना टैरिफ लगाया है, लेकिन सौ देशों ने इसे चुपचाप मान लिया। भारत सहित पांच देश अभी भी अमेरिका की इस जोर जबरदस्ती के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। ट्रंप के इस रवैये की जहां रूस ने आलोचना की है, वहीं अब ईरान भी भारत के समर्थन में आ गया है। भारत में ईरान के राजदूत डॉ. इराज इलाही ने कहा है कि अमेरिका अर्थव्यवस्था को हथियार बना रहा है। उन्होंने भारत के खिलाफ टैरिफ को केवल एक देश का मामला न समझने कहा, बल्कि इससे कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत पर इस मनमाने टैरिफ का देश के निर्यात और कारोबार पर क्या और कितना असर होगा? इस बारे में विशेषज्ञों की राय अलग-अलग हैं। कुछ का मानना है कि भारी टैरिफ से भारत की जीडीपी में कुछ कमी आएगी तो कुछ के मत में भारत के लिए यह अवसर भी है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ तथा जी 20 के पूर्व शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत आर्थिक सुधारों की दिशा में लंबी छलांग लगा सकता है। इस संकट को पूरी तरह देशहित में इस्तेमाल करना जरूरी है। ट्रंप यह संदेश बार-बार दे रहे हैं कि भारत रूस के साथ अपने कारोबारी रिश्ते खत्म करे। अमेरिकी उत्पादों के लिए भारत का कृषि व डेयरी उद्योग खोले तथा ब्रिक्स में अपनी भूमिका समेटे। जाहिर है कि यह कतई संभव नहीं है कि दुनिया में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत अमेरिका के आगे घुटने टेकेगा और अपने आजमाए हुए दोस्त रूस से रिश्ते बिगाड़ेगा। यहां तक कि भारत चीन से भी अपने सम्बन्ध सुधारने की कोशिश में है। इसका संकेत इसी बात से मिलता है कि पीएम मोदी इस बार एससीओ की बैठक में भाग लेने चीन जाएंगे। वैसे भी अमेरिका का अब तक रवैया आमतौर भारत विरोधी ही रहा है। और फिर ट्रंप जैसे मानसिक रूप से भी अस्थिर व्यक्ति की बातों पर किस आधार पर भरोसा किया जाए। ट्रंप द्वारा भारत की नाक दबा कर रूस का मुंह खुलवाने की कोशिश बचकानी है। वह भारत को चिढ़ाने के लिए पाक सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बार-बार अमेरिका न्यौता रहा है। वैसे पाकिस्तान की अमेरिका से बढ़ती दोस्ती पर चीन की भी गहरी नजर है। उधर अमेरिका में भी भारत के प्रति ट्रंप के रवैए की आलोचना हो रही है। लेकिन ट्रंप अपनी सनक में काम किए जा रहे हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि दबाव में भारत न कभी झुका है और न ही झुकेगा।

कर्तव्य बोध का उज्ज्वल पक्ष

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

अब समय बदला है। अब भारत में मानसिक रूप से एक अलग तरह की जो पीढ़ी तैयार हो रही है वह इसे कर्तव्य पथ ही जानेगी और उसके भीतर कर्तव्य के प्रति भावना भी अंकित होगी। यह सोच के स्तर पर बदलाव को सरकार ने जो बदलने का यत्न किया वह सराहनीय है और इसकी सराहना हुई भी है। अब देश में उसी कर्तव्य पथ की तर्ज़ पर कर्तव्य भवन का निर्माण हुआ और उसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री ने किया। यह राष्ट्र को समर्पित भवन दिल्ली में राजधानी की न तो शोभा बने और न ही केवल एक ईंट-पत्थर की ईमारत। यह भवन यदि सच में देश के डेढ़ अरब आबादी को यह सीख दे कि भारत में कर्तव्य बोध, भारत बोध है और इसके लिए हमें अपने समर्पित जीवन को देश के लिए लगाना है तो बात अच्छी होगी। वरना देश में बने अनेक भवनों, ईमारतों, आश्रमों के होने से कुछ भी होने वाला नहीं है।

दिल्ली में कर्तव्य पथ, देश के नए संसद भवन, नए रक्षा भवन, भारत मंडपम्, यशोभूमि, शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल, नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा और अब ये कर्तव्य भवन राजधानी की शोभा बढ़ाने लगे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा निर्मित इन कार्ययोजना के पीछे निहित उद्देश्य यह रहा है कि हम राष्ट्रबोध को समझें और राष्ट्र के नायकों को समझें। राष्ट्रबोध ही वस्तुतः कर्तव्य-बोध का द्योतक है। अभी तक राजपथ से कर्त्तव्य पथ के रूप में मानसिक रूप से विनिर्मिति के पीछे इस सरकार की मंशा रही है कि पहले व्यक्ति अपने भीतर जमीनी सोच को पैदा करे। अपने भीतर भावनाओं को जागृत करे व उस पर विजय हासिल करे। कर्तव्य पथ बनाने के पीछे यही उद्देश्य रहा है।

अब समय बदला है। अब भारत में मानसिक रूप से एक अलग तरह की जो पीढ़ी तैयार हो रही है वह इसे कर्तव्य पथ ही जानेगी और उसके भीतर कर्त्तव्य के प्रति भावना भी अंकित होगी। यह सोच के स्तर पर बदलाव को सरकार ने जो बदलने का यत्न किया वह सराहनीय है और इसकी सराहना हुई भी है। अब देश में उसी कर्तव्य पथ की तर्ज़ पर कर्त्तव्य भवन का निर्माण हुआ और उसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नी किया। यह राष्ट्र को समर्पित भवन दिल्ली में राजधानी की न तो शोभा बने और न ही केवल एक ईंट-पत्थर की ईमारत। यह भवन यदि सच में देश के डेढ़ अरब आबादी को यह सीख दे कि भारत में कर्तव्य बोध, भारत बोध है और इसके लिए हमें अपने समर्पित जीवन को देश के लिए लगाना है तो बात अच्छी होगी। वरना देश में बने अनेक भवनों, ईमारतों, आश्रमों के होने से कुछ भी होने वाला नहीं है।

यह भवन हमसे आग्रह करता है कि हम अच्छे मन से, अच्छे कर्म से और अच्छे कार्यशैली से जाने जाएँ। यदि देश में कोई आश्रम बनाए और वहां के आश्रम के लोग चारित्रिक रूप से बुरे हों, अपने भौतिक आनंद में डूबे हों, तो आश्रम एक दिन निंदा का पात्र बन जायेगा और वहां के मठाधीश जेलों के पीछे होंगे। भारत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं आश्रमों के भी जहाँ के स्वयंभू धर्माचार्य जेलों में हैं। वे खूब पूजे जाते थे लेकिन आचरण ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। भारत का कर्तव्य भवन भी जो बना है, यदि यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी, अधिकारी लोग ठीक आचरण करके देश के लोगों को सहयोग करेंगे, अच्छे आचरण से रहेंगे, अच्छे जीवन जिएंगे, भ्रष्टाचार आदि से दूर रहेंगे तो इसकी पहचान आने वाले समय में होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो कर्तव्य भवन के भी चर्चे लोगों के बीच, समाज में, राष्ट्र में निंदा का पात्र बनकर रह जाएगा।

भारत के प्रधानमंत्री ने इस भवन के उद्घाटन अवसर पर बहुत विनम्र भाव प्रकट किया है। वे सभी भाव शब्द-शब्द मोती की भांति हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने इस इमारत को बहुत मंथन के बाद 'कर्तव्य भवन' नाम दिया है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, ये नाम हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की मूल भावना का उद्घोष करते हैं। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नान-वाप्तं अ-वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि॥ अर्थात्, हमें क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त नहीं करना है, इस सोच से ऊपर उठकर हमें कर्तव्य भाव से कर्म करना चाहिए। कर्तव्य, भारतीय संस्कृति में ये शब्द केवल दायित्व तक सीमित नहीं हैं। प्रधान मंत्री का मानना है कि कर्तव्य, हमारे देश के कर्मप्रधान दर्शन की मूल भावना है। स्व की सीमा से परे, सर्वस्व को स्वीकार करने की विराट दृष्टि, यही कर्तव्य की वास्तविक परिभाषा है। और इसलिए, कर्तव्य, ये सिर्फ इमारत का नाम भर नहीं है। ये करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि है। कर्तव्य ही आरंभ है, कर्तव्य ही प्रारब्ध है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म, वही तो है- कर्तव्य। सपनों का साथ है- कर्तव्य, संकल्पों की आस है- कर्तव्य, परिश्रम की पराकाष्ठा है- कर्तव्य, हर जीवन में ज्योत जला दे, वो इच्छाशक्ति है- कर्तव्य। करोड़ों देशवासियों के अधिकारों की रक्षा का आधार है- कर्तव्य, मां भारती की प्राण-ऊर्जा का ध्वजवाहक है- कर्तव्य, नागरिक देवो भवः के मंत्र का जाप है- कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है- कर्तव्य।

देश में अभिमंत्रित शब्दों के साथ, अच्छे मन से प्रधान मंत्री ने इस कर्तव्य भवन को सौंपा है। इतनी सारी व्याख्या भी कर दी और लोगों को यह जता भी दिया कि हम क्या करें। देखा जाए तो भारत के शिल्प में इस भवन को ऐतिहासिक स्थान मिलने वाला है। आने वाला वक्त जब भी इस भवन के सन्दर्भ में स्मरण होगा तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी शब्द भी दुहराए जाएंगे। इस प्रकार नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश को सनातन मार्गी बनाकर हम सबके समक्ष प्रकट कर दिया। अब ये शब्द आने अली पीढ़ी, बाद की पीढ़ी, पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्मरित किए जाएंगे और आज के मंतव्य को आगे भी प्रसारित-प्रचारित करेंगे। भारतीय प्रसार परंपरा भी कुछ ऐसी ही है। भारत के धर्म, अध्यात्म और लोक की बातें हमें इसी क्रम में विरासत में प्राप्त कर ली है, हमें पता नहीं चलता है। अब सवाल यह है कि प्रधान मंत्री ने जिन अभिमंत्रित शब्दों के साथ राष्ट्र को यह भवन समर्पित किया, क्या उसे हम निभाने के लिए मनोयोग से तत्पर हैं? क्या हम अपने आचरण का हिस्सा बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्या यह भवन आने वाले समय में किसी भी ऐसे कुविचार, कुकृत्य व कुसंस्कार के लिए नहीं न उद्धृत किया जाएगा? यह विचार इसलिए हमारे मन में आते हैं क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं भारतीय लोग मन, कर्म और वचन में एकत्व नहीं रखते। भारत की लाज के लिए, प्रधानमंत्री के शब्दों की प्रतिष्ठा के लिए ही सही, यदि सभी यहाँ कार्यरत लोगों ने प्रधानमंत्री के शब्द को बार-बार याद रखा और उसे आचरण का हिस्सा भी बनाया तो, ऐसे कोई भी स्वर आने वाले दिनों में हमें सुनने या सुनाने के लिए नहीं बनेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि सभी अनुशासित, सतर्क व व्यवस्थित जीवन जिएं और इस भवन की गरिमा को बनाकर रखें।

इस भवन के साथ प्रधान मंत्री ने कुछ और बातें भारत के विश्वास व भविष्य के रोडमैप के लिए कही। प्रधान मंत्री का मानना है कि जब सफल राष्ट्र आगे बढ़ते हैं, तो अपनी सकारात्मक विरासत को त्यागते नहीं हैं। वो उसे संरक्षित करते हैं। आज विकास और विरासत के इसी विज़न पर हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। नए कर्तव्य भवन के बाद ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भी भारत की महान विरासत का हिस्सा बनेंगे। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को देश की जनता के लिए यगे युगीन भारत, इस संग्रहालय के रूप में बदला जा रहा है। देश का हर नागरिक यहाँ जा सकेगा, देश की ऐतिहासिक यात्रा के दर्शन कर सकेगा। प्रतिभागिता, साझेदारी, आशा व विश्वास से ही तो कोई राष्ट्र आगे बढ़ता है। कर्तव्य भवन का भी उदय कुछ इसी प्रकार हुआ है। भारत के लोगों का दायित्व है कि वे इसके माहात्म्य को बढ़ाएं। भारत का सामर्थ्य बढ़ाएं। भारत को भारत की विरासत का बचाव करके अच्छे अभिव्यक्ति के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है।

शिबू सोरेन का निधन

झारखंड की राजनीति के महानायक की विदाई

डॉ. ललित कुमार

लेखक इन्वर्टिस विश्वविद्यालय बरेली में पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष हैं।

झारखंड में बारे में अक्सर कहा जाता था, जब से झारखंड को अलग राज्य का दर्जा हासिल हुआ है, तब से लेकर यहां कभी भी स्थाई सरकार नहीं रही। यानी 21वीं सदी के डेढ़ दशक तक झारखंड की राजनीति कभी स्थिर रही ही नहीं। इसमें कोई दोराय नही हैं, यहां एक के बाद एक लगातार सरकारें बनती और गिरती रही है। यह सिलसिला लगभग पिछले डेढ़ दशक तक यूं ही चलता रहा। हाई वोल्टेज ड्रामा वाली राजनीति के लिए झारखंड जाना जाता था, जिस कारण झारखंड की राजनीतिक छवि पूरे देशभर में धूमिल होने लगी थी, और जनता ने कहना शुरू कर दिया कि अब यहां की राजनीति सिर्फ गुड्डे गुड़ियों का खेल बनकर रह गई है।

15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ, तब से लेकर इन 25 सालों में 12 मुख्यमंत्री बने है। अब इसे झारखंड की राजनीति का नसीब कहे या दुर्भाग्य। जिनमें तीन बार राष्टपति शासन लगना भी शामिल है। झारखंड पूरे देश की खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों के तौर पर सबसे खूबसूरत राज्य माना जाता है। झारखंड में कोयला और अन्य खनिज पदार्थ बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। झारखंड के कुछ हिस्से आज भी ऐसे है जहां पर सोने की खान है। यानी झारखंड को सोनार बनाने का सपना संजोय दिशोम गुरु (शिबू सोरेन) ने 4 अगस्त 2025 को दुनिया से अलविदा कह दिया। दिशोम गुरु नाम से विख्यात झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने राज्य को मजबूत बनाने और आदिवासी समाज की हकमारी के खिलाफ कई बड़े आंदोलन खड़े किये।

झारखंड की राजनीति का ऐसा जाना पहचाना नाम, जो आदिवासी समाज के अस्तित्व को बचाने और उनके हितों की रक्षा के लिए कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहा। कहा यह भी जाता है कि झारखंड की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले शिबू सोरेन के संघर्ष को समझना बेहद जरूरी है, जिन्होंने अपने परिवार की चिंता के साथ-साथ पूरे आदिवासी समाज की भी चिंता की।

झारखंड राज्य की अलग मांग के लिए शिबू सोरेन उन शीर्ष नेताओं में से एक रहे हैं, जिन्होंने जल, जंगल, जमीन और महाजनों से आदिवासी जमीन को छुड़वाने के लिए हिंसात्मक तरीके से आंदोलन किये, साथ ही वह आदिवासियों के अधिकारों के लिए संसद में उनकी आवाज़ भी बने। यानी आदिवासी राजनीति को नई दिशा देना का काम भी शिबू सोरेन ने किया। झारखंड में तीन बार के मुख्यमंत्री के तौर वह मात्र10 महीने यानी 308 दिन ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। शिबू सोरेन की पहचान झारखंड में गुरु जी के तौर पर जानी जाती थी। उनके समर्थक उनको सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि एक आंदोलनकारी, समाज सुधारक और जननेता के तौर पर ज्यादा जानते थे। आदिवासी समाज में शिबू सोरेन को गुरु जी कहकर पुकाराना एक संबोधन बन गया था। शिबू सोरेन (शिवचरण मांझी) आदिवासी समाज को शिक्षित करना चाहते थे। वह हमेशा अपने भाषण में कहा करते थे कि पढ़ो रे.... हडिया छोड़ो रे... यानी गुरु जी आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए रात्रि में पाठशाला चलाते थे। ताकि समाज का युवा वर्ग शिक्षित होकर अपने कुल की रक्षा पढ़ लिखकर कर सके। झारखंड का यह माटी पुत्र आगे चलकर आदिवासी समुदाय का आत्मगौरव और अस्मिता का बड़ा पैरोकार बना।

शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति में अब एक ऐसा अध्याय बन गये है। जिन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जायेगा। 70 के दशक में जब झारखंड राज्य की अलग मांग का मुद्दा बड़ी तेजी से बढ़ने लगा था, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा, बागुन सुम्ब्रई, एनई होरो सहित कई ऐसे बड़े नेता इस आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन शिबू सोरेन के आने से इस आंदोलन में और तेजी देखने को मिली। विनोद बिहारी महतो, एके राय और शिबू सोरेन ने मिलकर 4 फरवरी 1972 को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन किया, जिसमें विनोद बिहारी महतो को पार्टी अध्यक्ष और शिबू सोरेन को महासचिव बनाया गया।

शिबू सोरेन ने संथाल परगना में अपनी राजनीतिक जमीन को खून पसीने से सींचकर मजबूत किया। इसलिए उनके राजनीतिक कद को आगे बढ़ाने में संथाल परगना की बड़ी अहम् भूमिका रही। शिबू सोरेन वर्ष 1980 में झारखंड की दुमका लोकसभा सीट से जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर शिबू सोरेन आदिवासी राजनीति का एक ऐसे चेहरा बनकर उभरे, जिसे आदिवासी समाज को बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, यानी शिबू सोरेन की बदौलत ही आदिवासी समाज को सम्मान और उनकी राजनीति को राष्ट्रीय पहचान मिल सकी।

झारखंड की आदिवासी अस्मिता और सामाजिक संस्कृति के पैरोकार के रूप में शिबू सोरेन के संघर्ष की कहानी नेल्सन मंडेला से काफी मेल खाती है। यानी वास्तव में शिबू सोरेन झारखंड के नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने शोषित व पीड़ित आदिवासी समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए शिक्षा को हथियार बनाया। उनका सबसे ज्यादा जोर युवाओं को शिक्षित करने पर रहा। इसलिए उन्होंने शिक्षा और सामाजिक एकता को ढाल बनाकर अपनी राजनीति को ओर मजबूत किया। पेशे से शिक्षक पिता (सोबरन मांझी) की हत्या, गांव के महाजनों सूदखोरों व दबंग ठेकेदारों द्वारा की गई, का बदला शिवचरण मांझी ने शिबू सोरेन बनकर समाज को एकजुट करके लिया। झारखंड की लगभग 30 फ़ीसदी आदिवासी समुदाय की जनसंख्या के समीकरण को दिमाग में रखते हुए शिबू सोरेन ने गांव के रसूखदार व महाजनों को निशाना बनाया, जिसके बाद झारखंड में जमीन मुक्ति आंदोलन ने जिस तेजी से जोर पकड़ा था, उसने पूरे झारखंड में हलचल पैदा कर दी थी। यानी झारखंड में शिबू सोरेन की राजनीतिक छवि एक ऐसे बड़े नेता के तौर उभरने लगी थी, जिसके बाद शिबू सोरेन ने झारखंड के दूर-दराज इलाकों में जाकर लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया, जहां का वंचित समाज महाजनी प्रथा से बहुत त्रस्त आ चुका था। शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन को तेज करने के लिए बोकारो के जैना मोड को अपना केंद्र बनाया।

संथाल परगना का चिरुडीह कांड संथाल विद्रोह की क्रांति का एक ऐसा जीता जागता उदाहरण बना, जिसके बाद शिबू सोरेन इस आंदोलन के महानायक बने। 23 फरवरी 1975 को चिरुडीह कांड हुआ, जिसके बाद शिबू सोरेन ने महाजनों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। इसका नतीजा यह रहा कि झारखंड में जहां भी दबंगों ने आदिवासियों की जमीने कब्जाई थी, उनको वे सब जमीने छोड़नी पड़ी। इस कांड के बाद से शिबू सोरेन की आदिवासी राजनीति का सितारा राष्ट्रीय स्तर पर चमक उठा। 2 फरवरी 1979 को दुमका में जब पहली बार मंडलीय स्तरीय रैली हुई। उसमें बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने दुमका जाकर शिबू सोरेन के साथ मंच साझा करते हुए कहा था। शिबू सोरेन भविष्य में झारखंड के आदिवासी समाज के एक महान नेता साबित होंगे। यानी शिबू सोरेन ने अपने जीवन में जो सपना देखा, उसे उन्होंने काफी हद तक पूरा किया, जिसमें महाजनी प्रथा को खत्म करके आदिवासी समाज को मान सम्मान से जीने के लिए तैयार करना और झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाना शामिल है। जिसमें शिबू सोरेन को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। इसी सम्मान को पाने के लिए आदिवासी समुदाय झारखंड के युग पुरुष शिबू सोरेन के संघर्ष को कभी नहीं भूल पाएगा।

स्वदेशी से तरक्की

आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ता भारत

डॉ.परविंदर शर्मा

लेखक भगवान श्री परशुराम चेयर जगत गुरु नानक देव पंजाब राज्य मुक्त विश्वविद्यालय,पटियाला में सहायक प्रोफेसर हैं।

भारत एक प्राचीन सभ्यता और विविधताओं से भरा देश है जिसने सदियों से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी विचारधारा को अपनाया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने 'स्वदेशी आंदोलन' के माध्यम से भारतवासियों को विदेशी वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह सिर्फ एक आर्थिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह आत्मगौरव, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक भी था। 'स्वदेशी' शब्द संस्कृत भाषा से आया है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है- 'स्व' का अर्थ है - अपना या स्वयं का 'देशी' का अर्थ है - देश से संबंधित या स्थानीय। स्वदेशी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। विशेष रूप से यह शब्द 1905 के बंग-भंग आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था। इसके विरोध में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने जनता से विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की। आज, जब वैश्वीकरण की दौड़ में भारत कई विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिला रहा है, तब एक बार फिर 'स्वदेशी से आत्मनिर्भरता' की ओर बढ़ना समय की माँग बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को न केवल आर्थिक रूप से मज़बूत बनाना चाहता है, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर एक सक्षम और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। महात्मा गांधी के अनुसार, स्वदेशी न केवल आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक था, बल्कि यह एक नैतिक कर्तव्य भी था। उनका मानना था कि यदि हम अपने देश के कारीगरों, किसानों, और उद्योगों को समर्थन देंगे, तो हम एक मज़बूत राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे।

स्वदेशी आंदोलन ने न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, बल्कि भारत में छोटे-छोटे उद्योगों को जन्म दिया, खादी को पुनर्जीवित किया, और स्थानीय उत्पादन को महत्ता दी। आज, इस विचार को आधुनिक संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था - एक ऐसा भारत जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके, वैश्विक संकटों का सामना कर सके और 'वोकल फॉर लोकल' के सिद्धांत पर चल सके। इस अभियान के पाँच स्तंभ अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, जनसांख्यिकी, मांग। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आत्मनिर्भर भारत की नींव भी स्वदेशी सोच पर आधारित है। जब हम स्थानीय उत्पादन को प्राथमिकता देते हैं, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, कृषि, हस्तशिल्प, खादी, और स्टार्टअप्स को समर्थन देते हैं, तो हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं। आज भारत में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएँ भी इस दिशा में सहायक हैं। ये योजनाएँ देश के युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित करती हैं और नवाचार को बढ़ावा देती हैं। स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत के लिए हमे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना स्थानीय कारीगरों, किसानों, और उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों का उपयोग करना। स्वदेशी उद्योगों को समर्थन जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को तकनीकी, वित्तीय और विपणन सहायता देना। स्टार्टअप्स और नवाचारों को बढ़ावा देना। स्वदेशी तकनीक और अनुसंधान में निवेश विज्ञान, तकनीक और नवाचार को देश में विकसित करना। आत्मनिर्भर रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान को समर्थन देना।आयात पर निर्भरता कम करना, उन वस्तुओं का घरेलू उत्पादन बढ़ाना जिन्हें अभी तक आयात किया जाता है।विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करके घरेलू विकल्प अपनाना, भारतीय उपभोक्ताओं में स्वदेशी के प्रति जागरूकता, उपभोक्ताओं को यह समझाना कि स्वदेशी उत्पाद न केवल गुणवत्ता में बेहतर हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती देते हैं। मीडिया और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवादी उपभोग संस्कृति को बढ़ावा देना। जिस के कारण हम भारतीय संस्कृति और हमरे कल्चर को मजबूत कर सकते है और लक्ष्य को पा सकते हैं।

स्वदेशी से आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा सिर्फ आर्थिक विकास का मार्ग नहीं है, यह आत्मगौरव, आत्मबल और राष्ट्रनिर्माण की भावना से जुड़ी है। जब हर भारतीय स्थानीय उत्पादों को अपनाने, अपने कारीगरों और उद्यमियों को समर्थन देने और भारतीय ब्रांड्स को वैश्विक मंच पर लाने का संकल्प लेता है, तभी सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव है। स्वदेशी को केवल एक उत्पाद खरीदने की आदत न मानकर एक राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में देखा जाए, तो भारत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त हो सकता है। यही भविष्य का भारत होगा- आत्मनिर्भर, आत्मबलशाली और आत्मगौरव से भरा हुआ। जय हिंद जय भारत।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

चेनू उर्फ भईया उर्फ भगवान

जवाहर चौधरी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

अपने 'भईया-लोग' भगवान तो नहीं पर भगवान से कम भी नहीं हैं। लोग कहते हैं कि देश भगवान भरोसे चल रहा है तो अनुभवीजन बिना देर किये इसकी गहराई को समझ जाते हैं। मानो तो भगवान जी हैं, न मानों तो जोखिम आपका। कवाडें बुलंद हों तो पुलिस जनसेवक है, न हों तो अंतिम सत्य राम है । समझदार को इशारा काफी होता है । तो बोलो? शांति?, शांति शांति ?

बराबरी, स्वतंत्रता और सहयोग के इरादे से शुरू हुए लोकतंत्र में भईया भगवान हो गए यह बिकास नहीं महाबिकास है । चैनसिंग उर्फ चेनू उर्फ भईया उर्फ भगवान आज टीवी मीडिया से मुखातिब हैं। कल विपक्ष के एक नेता मीडिया के सामने कह गए थे कि कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है और सरकार गुंडों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। जो जेल में सुरक्षित रहता है वो अस्पताल में मारा जाता है। असामाजिक तत्वों ने आमजन का भी जीना मुश्किल कर दिया है। इसी के जवाब में आज मंच पर फैले चेनू अपनी बात रख रहे हैं।

'एक बात समझ लो आप लोग अच्छी तरह से कि जिसे ये लोग गुंडा-गुंडा कह रहे हैं उनकी सोच पुरानी है। अब गुंडा-कर्म एक कमाऊ इंडस्ट्री है देश की। गुंडे जी उच्चकोटी की समाज सेवा में लिप्त हैं। G-इंडस्ट्री जहाँ जहाँ काम कर रही है वहाँ हमारे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। सरकार कोई भी हो G-इंडस्ट्री सेवा कर डालने से पीछे नहीं हटती है । काम जिम्मेदारी से करते हैं, इसलिए हमारा नाम है।'

एंकर को अपनी जिम्मेदारी और खतरे पता है, बोली - 'सर दरअसल G-इंडस्ट्री के बारे में जनता को पता नहीं है! उनकी जानकारी में आप इजाफा कर सकते हैं ।'

'G-इंडस्ट्री समाज में एक सक्रिय, आत्मनिर्भर और हाई टर्नओवर कंपनी है। विपक्ष ने इसे असामाजिक तत्व कह कर अपमानित किया है । सही समय आने पर G-इंडस्ट्री इसका हिन्दी में जवाब देगी। उन्हें यह देखना चाहिए कि देश बेरोजगारी के संकट से गुजर रहा है। एक हमारी इंडस्ट्री ही है जिसने युवा हाथों को काम दिया है। क्या ये देश सेवा नहीं है! मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि है। यहाँ कोई असहमत हो तो सामने आ कर अपनी बात रखे।' चेनू ने हॉल में नजर दौड़ते हुए कहा।

एंकर को कोई बात नहीं सूझती है। ऐसे मौकों पर मुस्कराहट काम में लेती हैं, -'दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में खासतौर से G-इंडस्ट्री के सीईओ चेनू सर मेहमान हैं और मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं। ... तो सर आपने बताया कि आपकी इंडस्ट्री इसलिए फलफूल रही है क्योंकि देश में बेरोजगारी है ।'

'गरीबी बेरोजगारी पॉलिटिकाल इंडस्ट्री का रॉ-मटेरियाल है। चुनाव में यूज करने के बाद बाकी टाइम में ये लोग हमारे काम आते हैं। मतलब गरीब सेकंड हेंड, बेरोजगार सेकंड हेंड हम वापर लेते हैं। हम चाहते हैं इनकी मदद हो, सबका कल्याण हो। नेता भी खुश रहें, धरम-धंधे वाले भी, साथ में गरीब और बेरोजगार भी। अपने अपने पेट के हिसाब से सबको भरावन मिले। इसमें कोई बुराई है क्या ?'

'बुराई तो नहीं है सर, लेकिन आप दूसरे अच्छे काम भी तो करवा सकते हैं इनसे।'

'नजरिया बादलों आप लोग। अच्छे काम ही करते हैं। हमारी वजह से ही पुलिस को रोजगार मिला हुआ है, जेलों का कारोबार चलता है, अस्पतालों को हड्डियों के ज्यादातर केस कौन देता है, चाकू कट्टे की फेक्टरी में रोजगार किसकी वजह से है ... और बताओ जरा सरकारें कौन बनवाता है ?'

'सर ऐसी क्या बात है। अब तो सरकार हम भी बनवाते हैं।' टीवी एंकर ने मुस्कराते हुए कहा ।

'गलतफहमी कोई भी पाल सकता है।' ceo बोले ।

भारत छोड़ो आंदोलन के 83 वर्ष

डॉ.ब्रह्मदीप अलूने

('गांधी है तो भारत है' किताब के लेखक)

इस बार ट्रम्प की भारत से विदाई तय है

प्रत्येक राष्ट्र का यह मौलिक अधिकार है की वह अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने भौगोलिक वातावरण,प्राकृतिक संसाधनों,वन,जल,खनिज,मानव संसाधन और कृषि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे और उचित दामों पर वस्तुओं की उपलब्धता से आम जनता को खुशहाल करें। महात्मा गांधी के लिए हर गांव एक राष्ट्र था। वे गांवों को अधिकार सम्पन्न बनाकर ग्रामीण लोगों के हाथों में वहां के विकास की डोर सौंपना चाहते थे जिसमें सभी वर्ग और जातियों के लोग मिलाकर पूरे अधिकार से अपने भाग्य का फैसला कर सके। बापू के लिए स्वदेशी से तात्पर्य अपनी ताकत पर निर्भर रहना था। 28 जुलाई 1946 को एक साक्षात्कार में महात्मा गांधी ने कहा था,प्रत्येक गांव पूर्ण शक्तिवाला गणतंत्र या पंचायत होगा। इसलिए प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर और अपना काम खुद सम्भालने में सक्षम होना पड़ेगा।

ट्रम्प अपने पहले कार्यकाल में 2020 में जब भारत आएं थे तो उन्होंने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मलबार शाहबलूत का पौधा लगाया था। इस पौधे को शुभ और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है जो धीरे धीरे बड़ा होकर उंचाई को छू लेता है। बापू के कार्य भी धीरे-धीरे परिणाम देते थे और अंततः यह बेहतरी के अवसर ढूंढ लाते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अतिथि पुस्तिका में लिखा था,अमेरिका की चाहत है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे। काश,ट्रम्प भारत की समृद्धि को भारत के किसानों की दृष्टि से देख पाते तो बेहतर हो सकता था।

दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मूल विचार से बहुत दूर नजर आती है। इसका प्रमुख कारण भारत की बड़ी आबादी का कृषि पर निर्भरता रहा है जो व्यवसाय से कहीं ज्यादा करोड़ों लोगों के जीवन जीने का साधन है। अमेरिका में वाणिज्यिक कृषि होती है जबकि भारत निर्वाहन खेती पर निर्भर है। यह लाखों भारतीयों की आजीविका है जबकि अमेरिका में कृषि वैसा ही व्यवसाय है जैसा अन्य व्यवसाय। भारत में नब्बे फीसदी जोत के मालिक छोटे किसानों के पास निवेश की क्षमता नहीं है और निजी क्षेत्र को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत में किसानों का आत्मविश्वास बनाएं रखने के लिए उनसे सस्ती दरों में अनाज खरीदने सरकारी योजनाओं के तहत किया जाता है,किसानों को सस्ती बिजली दी जाती है और उन पर दबाव न बढ़े,इस कारण बिजली बिल कभी कभी माफ़ भी कर दिए जाते है। अमेरिका का किसान चुनावों में फंडिग करता है,वह इतना समृद्ध है की एक दबाव समूह की तरह वह काम करता है ।

ट्रम्प राजघाट जाकर,पौधा लगाकर दुनिया के सबसे बड़े देश लोकतांत्रिक देश के किसानों की समृद्धि को लेकर कोई योजना प्रस्तुत करते तो दोनों देशों के बीच विश्वास भी बढ़ता और व्यापार बढ़ने के अवसर भी बढ़ते। लेकिन ट्रम्प की नजर भारत की कृषि पर है। वे भारत के छोटे किसानों के बराबर अमेरिका के किसानों को सुविधा देने की सौदेबाज़ी करना चाहते है,जो न तो नीतिगत तरीके से संभव है और न ही ऐसी किसी योजना पर सरकार अमेरिका के साथ सहयोग करने के बारे में सोच सकती है। ट्रम्प गांधी की उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर चोट करना चाहते है जो भारत की सशक्तिकरण और बेहतरी का कारण है। ट्रम्प की दृष्टि में भारत का कृषि बाजार एक विशाल व्यापारिक अवसर है,एक ऐसा क्षेत्र जहां अमेरिकी बीज, कीटनाशक, कृषि मशीनरी और खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां अपने उत्पाद बेच सकती हैं और स्थानीय किसानों को अपने मॉडल में बांध सकती हैं। गांधीजी का स्वराज का सपना आत्मनिर्भर किसान था,लेकिन ट्रम्प की व्यापारिक दृष्टि भारत के गरीब और दो जून की रोटी अपने खेतों में तलाशने वाले किसान को विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर बनाने पर है।

भारत का समग्र विकास बिना ग्रामीण विकास के संभव नहीं है। यह ग्रामीण विकास तभी प्राप्त किया जा सकता है,जब गांधी के ग्राम स्वराज को अपनाया जाएं। गांधीजी की कल्पना का ग्राम स्वराज मानव केंद्रित है, जबकि पश्चिमी अर्थव्यवस्था धन केंद्रित है। विश्व के

अधिकांश राजनीतिज्ञ ऊपर से नीचे की ओर योजनाओं को चलाकर विश्व शांति की आकांक्षा की बात करते है,जबकि महात्मा गांधी की सारी योजनाएं नीचे से ऊपर की दिशा में काम करती है। इसलिए उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता नीचे से आरंभ होनी चाहिए। बापू भारत की महानता और सशक्तिकरण को गांवों की मजबूती में देखते थे। जिन्हें अंग्रेजों ने नष्ट करने के कई कोशिशें की थी।

हमारे गांव 1857 के पहले तक नमक,मेवा जैसी चीजों को छोड़कर पूरी तरह आत्मनिर्भर थे और हम कपड़ा,शौरा,अफीम,खांड,मसालें जैसी न जाने कितनी चीजें बाहर भेजते थे। 1836 में ब्रिटिश गवर्नर ने एक अख़बार में लिखा कि भारत का प्रत्येक गांव अपने आप में एक गणतंत्र है। यह अपनी न्यूनतम जरूरतों के लिए किसी अन्य गांव,यहां तक की पड़ोस पर भी निर्भर नहीं है। एक गांव की मूलतः तीन जरूरतें है,रोटी,कपड़ा और मकान। एक गांव अपने भोजन के लिए अनाज उगा सकता है,रहने के लिए घर बना सकता है,और कपड़े के लिए कपास उगा सकता है। इस प्रकार हर गांव अपने आप में आर्थिक स्वावलम्बी होता है।

हिन्द स्वराज में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा पोषित आधुनिक सभ्यता की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने अपनी भारत भ्रमण के दौरान यह पाया की किस प्रकार ब्रिटिश आधिपत्य ने भारत के लघु और कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया है। ट्रम्प भी ब्रिटिश आधिपत्य की राह पर चलते है अपने अपने टैरिफ के दबाव का इस्तेमाल कर रहे है। भारत अपने मेहनतकश किसानों को किसी भी मुक्त व्यापार समझौते से दूर ही रखता है क्योंकि इसे हमारे भोले भाले किसान फंस सकते है और यह हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है,अंततः कृषि देश की आधी से ज्यादा बढ़ी आबादी की जीविका का आधार है। भारत अपने कृषि क्षेत्र को अमेरिकी कंपनियों से बचाने के लिए वहां से होने वाले कृषि उत्पादों के आयात पर बड़ा टैरिफ लगाता है। अंग्रेजों को भारत की ताकत गांवों में नजर आती थी इसलिए उन्होंने छोटे उद्योग धंधों को नष्ट करके भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर चोट करने की कोशिश की थी और बापू आम हिन्दुस्तानी को ग्राम स्वराज की ताकत का एहसास कराने और विश्वास बढ़ाने हजारों किलोमीटर पैदल चलते रहे,उतना जितने में वे दो बार पूरी दुनिया घूम सकते थे।

गांवों को लेकर बापू की स्पष्ट दृष्टि थी की इसकी सम्पन्नता और खुशहाली ही भारत की सभी समस्याओं का इलाज है। वे भारत के कोने कोने में गए और उन्होंने यह पाया की भारत की बहु आबादी ग्रामीण है और उसमें मेहनत और स्वावलम्बन कूट कूट कर भरा है। बापू का सेवाग्राम में रहने का इरादा और संदेश साफ था की शहर के लोगों को ग्रामीण जन से आत्मनिर्भरता,कृषि और पर्यावरण संरक्षण सीखना चाहिए। गांव की सादगी और यहां रहने वाले लोगों की कार्य कुशलता से भारत का स्वर्णिम गौरव पुनः लौट सकता है। 8 अगस्त, 2025 को भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन के 83 बरस पूरे कर लिए है। इन वर्षों में भारत ने नित नए आयाम स्थापित किए है और संकल्पित होकर देश निरंतर प्रगति के पथ पर है। करीब दो सौ वर्षों तक अंग्रेजों की आर्थिक और राजनीतिक गुलामी के कुचक्र से भारतीय जूझते रहे लेकिन उन्होंने अपनी घर की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखा। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और यहीं कृषि अर्थव्यवस्था भी है। यह इसलिए टूट नहीं सकी क्योंकि ग्राम स्वराज भारत के तंत्र के मूल में है और यही ग्राम विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता रहा है। भारत आज़ाद हुआ तो देश की योजनाओं और परियोजनाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया और इसे लेकर सभी लोकतान्त्रिक सरकारें गंभीर रही,उन्होंने बापू के ग्राम स्वराज्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। ट्रम्प भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर चोट करके दोस्त बने रहने चाहते है,यह मुमकिन नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेज देश से भागने का मजबूर कर दिए गये थे,ट्रम्प की भारत से एक बार फिर ऐसी ही विदाई तय है। कर्ज से डूबे ब्रिटेन को पुनः खड़ा होने के लिए भारत से मुक्त बाज़ार समझौता करने को मजबूर होना पड़ा। भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाज़ार है और रणनीतिक रूप से भी बेहद खास है। ट्रम्प भारत की क्षमता और सामर्थ्य को बखूबी जानते है। अंग्रेजी सरकार के गहरें दबाव के बाद भी भारत छोड़ो आंदोलन तब तक समाप्त नहीं हुआ जब तक अंग्रेज देश छोड़कर जाने को मजबूर नहीं कर दिए गए। अब भारत आज़ाद है और अपने भाग्य का निर्माता खुद है। जाहिर है इस बार भी एक और अंग्रेज ट्रम्प भी भारत से विदाई तय है।

आज भरी थी 'भारत छोड़ो' की हुंकार

विशेष

डॉ. सुधीर सक्सेना

8 अगस्त महज एक दिनांक नहीं है। सन् 1942 में आजादी की लड़ाई ने इस तारीख को अपूर्व क्रांतिकारी भाव-भंगिमायें बख्शी थी। स्वतंत्रता के उद्दाम आवेग ने आठ अगस्त, 42 को उन ऊँचाइयों को छुवा था कि यह तारीख समय की पंजी में सुनहरे हरूफ़ में दर्ज हो गयी। आठ अगस्त को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने हुंकारी भरी 'अंग्रेजों भारत छोड़ो।' गूंज दूर दिल्ली नहीं, सात समुंदर पार बिलायत तक पहुंची। हुकूमत थर्रा उठी। द्वितीय विश्वयुद्ध चल रहा था। ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्र डिफेंस पर थे। उत्तर पूर्व सीमांत अंचल तक जापानी फौजें चढ़ आई थीं। नेताजी सुभाषचंद्र बोस आजाद हिन्द फौज के गठन के फेर में थे। महात्मा गांधी की इन सारी परिस्थितियों-घरेलू और वैश्विक मोर्चे पर पैनी निगाह थी। मार्च में आया क्रिप्स कमीशन विफल रहा था। किसी तरह ठोस आश्वासन दिये बिना वह बैरंग लंदन लौट गया था। असंतोष और अनिश्चिता चरम पर थी। बापू ने सारे देश में आजादी की लौ जगा दी थी। पूरा भारत रण क्षेत्र था और हर हिन्दुस्तानी योद्धा। ऐसे में बापू ने 'करो या मरो' का आवाहन कर गरम लोहे पर घन प्रहार किया।

भारत छोड़ो आंदोलन– बापू अद्भुत लोक-संचारक थे। उनके 'करो या मरो' और 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' की ललकार ने सारे देश में बिजलियां भर दी। अबुल कलाम आजाद, पं. जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल समेत सभी प्रमुख कांग्रेस-नेताओं को बंदी बना लिया। मगर आंदोलन ने जड़ें पकड़ लीं। उसे अगस्त क्रांति आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन के तौर पर जाना गया। कांग्रेस की मांगे क्या थी? ब्रिटिश राज का तुरंत अंत हो। प्रोवीजनल सरकार का गठन हो और भारत साम्राज्यवाद और फासीवाद से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करे। गौर करें कि बापू की नजरों में खतरा साम्राज्यवाद से था और फासीवाद से भी। वह इंपीरियलिज्म और फासिज्म को यकसां खतरनाक मानते थे। यह उनकी दूर दृष्टि थी। बहरहाल, उन्होंने अवाम से सविनय अवज्ञा की अपील की। शासकीय सेवकों से त्याग-पत्र नहीं देने पर कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता बरतने, किसानों से सिर्फ ब्रिटिश विरोधी जमींदारों को मानमाफिक लगान देने, छात्रों से पढ़ाई छोड़ने, युवराजों से जनता का समर्थन करनें और सार्वभौम मानने और प्रजा से सिर्फ ब्रिटिश विरोधी शासकों को समर्थन देने की अपीलें कीं।

भारत छोड़ों आंदोलन का देशव्यापी असर बाद में देखने को मिला, लेकिन उससे पेशतर एक बड़ी और क्रांतिकारी घटना घट गयी। अधिवेशन स्थल समेत चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात थी। लेकिन वीरता ने प्रतिबद्धता के बीच अपनी चमक दिखा दी। नौ अगस्त को एक निर्भीक युवती तीर की तरह प्रकट हुई और पाबंदियों और पुलिस को चकमा देते हुये उसने बंबई में अधिवेशन स्थल-गवालिया टैंक मैदान पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। यह युवती थी अरूणा आसफ अली। अरूणा आसफ अली समता, स्वतंत्रता, समाजवाद और सेक्यूलर मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नेत्री थी। उनका जीवनमूल्य परक था। सन 1930 और 1932 में वह जेल हो आई थीं। सन 1942 में उनकी आयु थी तैंतीस वर्ष। मजा देखिये कि गवालिया मैदान पर ध्वज फहराकर भी वह पुलिस के हाथ नहीं आईं और भूमिगत हो गयीं। भूमिगत रहकर भी उन्होंने आंदोलन जारी रखा। पत्रों, पोस्टरों और पर्चों के वितरण के अलावा उनका बड़ा काम था आजादी की अलख जगाने के लिए रेडियो प्रसारण। उन्होंने इन कामों को इतनी खूबी से अंजाम दिया कि पुलिस नाकामी में हाथ मलती रही। सरकार ने उनके सिर पर ईनाम रखा, लेकिन व्यर्थ। बेखौफ अरूणा बरसों बाद सन् 1946 में जनता के सम्मुख आईं। बाद में सन् 1958 में वह दिल्ली की पहली महिला महापौर चुनी गयीं। भारत छोड़ों आंदोलन ने उन्हें अद्भुत दृढ़ता प्रदान की। वह अफ्रो-एशियाई एकजुटता की प्रबल पैरोकार बनकर उभरीं। गोवा, दमण और दीव की मुक्ति के लिए उन्होंने राष्ट्रीय समिति का गठन किया। उन्होंने डेली पैट्रियट और साप्ताहिक लिंक का प्रकाशन प्रारंभ किया। दरअसल, भारत छोड़ो आंदोलन की आंच में तपकर अरूणा ही नहीं, जयप्रकाश नारायण और डॉ. राममनोहर लोहिया सरीखे नेताओं की नेतृत्व प्रतिभा भी निखरी। अरूणा, जेपी और लोहिया की 'त्रयी' को भारत छोड़ो आंदोलन ने कुंदन सा दमका दिया।

भारत छोड़ो आंदोलन छोटी मोटी घटना नहीं, क्रांतिकारी दौर था, जिसने समूचे भारत की रगो में क्रांतिकारी चेतना का संचार किया। बहशी सरकार के दमन का अंदाजा इससे लगायें कि सारे भारत में एक लाख से अधिक लोग बंदी बने। करीब दस हजार लोग पुलिस के बल प्रयोग में मारे गये। जनता ने बलिया, तामलुक, सतारा जैसी जगहों पर समांतर सरकार का गठन किया। कांग्रेस पर पाबंदी लगी। जनता स्वयं स्फूर्त सड़कों पर निकल आई। हुकूमत की मंशा के विपरीत कहीं कोई सांप्रदायिक फसाद नहीं हुआ। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग और हिन्दु महासभा ने आंदोलन से दूरी बरती और राजगोपालचारी जैसे नेता ने कांग्रेस छोड़ दी। गांधी जी स्वास्थ्य के आधार पर सन 44 में जेल से छूटे। इस बीच भारत छोड़ो आंदोलन ने आजादी की आधारशिला रख दी थी।

भारत छोड़ो की हुंकार से अंग्रेजों के पांवो तले से जमीन सरक चुकी थी। भारत स्वतंत्रता की देहरी पर था। बात दिलचस्प है, मगर सच है कि भारत छोड़ो का नारा गांधी के दिमाग की उपज नहीं था। यह यूसुफ मेहर अली नामक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ट्रेड यूनियन लीडर के दिमागी टकसाल की देन था। 'साइमन गो बैक' का नारा भी उन्होंने ही दिया था। वह बड़े ओजस्वी और प्रखर नेता थे। इसी का नतीजा था कि उन्हें उसी साल बंबई का मेयर चुना गया। महात्मा की खूबी कि उन्होंने एक श्रमिक नेता के गढ़े नारे को सारे देश का सामूहिक उद्घोष बना दिया।

आजादी का संघर्ष

भारत छोड़ो आंदोलन और गांधी

चित्रा माली

सहायक प्रोफेसर गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता।

1 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूज़वेल्ट को एक पत्र लिखा जिसके आरंभ में उन्होंने यह लिखा कि उनके कई मित्र और सहयोगी अमेरिका में पढ़ रहे हैं और वे खुद थोरो और इमर्सन के लेखन से बहुत लाभान्वित हुए हैं। इसके बाद गांधी ने आगे लिखा कि 'जब तक भारत और अफ्रीका का इंग्लैंड के द्वारा शोषण किया जाता रहेगा और अमेरिका में नीग्रो समस्या का समाधान नहीं होता,मित्र राष्ट्रों की वह घोषणा खोखली प्रतीत होती है जिसके तहत कहा गया है कि मित्र राष्ट्र विश्व में वैयक्तिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए यह युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति रूज़वेल्ट को प्रस्ताव दिया कि अगर भारत को आज़ाद कर दिया जाता है तो मित्र राष्ट्र भारत में सेना रख सकते हैं। ऐसा वे 'सिर्फ यहां की आंतरिक व्यवस्था बहाल करने के लिए नहीं करेंगे बल्कि ऐसा करने से जापानी आक्रमण और चीन की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी'। गांधी आगे लिखते हैं कि वे निजी तौर पर युद्ध और हिंसा के खिलाफ हैं लेकिन वे मानते हैं कि 'हर व्यक्ति का अहिंसा में विश्वास नहीं है'। ऐसे में वे भारतीय सरज़मी से जापानियों के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध के लिए राजी हैं, बशर्ते भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। गांधी ने यह पत्र लुइस फ़िशर के हाथों फ्रेंकलिन रूज़वेल्ट को पहुंचाया था। जुलाई 1942 के इसी प्रथम सप्ताह में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सेवाग्राम आश्रम में पहुंचे।

नौ दिनों के गंभीर विचार विमर्श के बाद 14 जुलाई को कांग्रेस की कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत से ब्रिटिश सत्ता की वापसी की मांग की गई थी। कार्य समिति ने कहा कि 'जब से युद्ध शुरू हुआ है कांग्रेस ने क्रमशः ऐसी नीति शुरू की थी कि अंग्रेजों को किसी भी तरह की अपमानजनक स्थिति से न गुजरना पड़े'। लेकिन अंग्रेजों ने इसके प्रत्युत्तर में भारत पर अपना शिकंजा और कस दिया। कांग्रेस ने धैर्यपूर्वक तीन साल के इंतजार के बाद यह आख़िरी प्रस्ताव दिया है कि अंग्रेजों को तत्काल भारत छोड़ देना चाहिए और उसके बदले में आज़ाद भारत की कोई भी 'अंतरिम सरकार' मित्र राष्ट्रों को जापानियों वे विरुद्ध भारतीय ज़मीन का सैन्य इस्तेमाल करने की इजाज़त देगी। कांग्रेस कार्य समिति ने यह आशा व्यक्त की कि अंग्रेज इस 'तार्किक और न्यायपूर्ण प्रस्ताव' को मान लेंगे जो न 'सिर्फ भारत के हित में है बल्कि ब्रिटेन के हित में भी है और उस आज़ादी के हित में जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव अपना समर्थन व्यक्त करता है'।

इसके विपरीत अगर 'इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है तो कांग्रेस हर तरह की अहिंसक शक्तियों के इस्तेमाल करने को अनिच्छुक रूप से विवश होगी ..... ताकि वह अपने राजनीतिक अधिकार और स्वाधीनता हासिल कर सके'। प्रस्ताव में कहा गया कि यह संघर्ष 'अनिवार्य रूप से महात्मा गांधी के नेतृत्व में होगा' और इसे कैसे लड़ा जाए उसका आख़िरी फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस समिति करेगी जिसकी बैठक बंबई में 7 अगस्त को निर्धारित है। इस समय सेवाग्राम में भारतीय और विदेशी दोनों पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्य समिति की बैठक के समाप्त होने के तुरंत बाद पत्रकारों ने गांधी को घेर लिया और उन पर सवालों की बौछार कर दी। सवाल-जवाब का यह दौर 14 जुलाई की शाम से शुरू हुआ और दूसरे दिन तक जारी रहा। जुलाई 1942 में ही गांधी एक भूख हड़ताल के बारे में गंभीरता से सोच रहे थे। हालांकि गांधी का लेखन इस ओर कोई संकेत नहीं देता कि वह भूख हड़ताल के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उनके अनुयायियों के पत्रों से ऐसा संकेत अवश्य मिलता है। 23 जुलाई को महादेव देसाई (भाई) ने इस आशय का एक पत्र अमृता कौर को लिखा जो उस समय अपने आवास शिमला में थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 जुलाई 1942 को अहमदाबाद और 2 अगस्त 1942 को बंबई के चौपाटी बीच पर भारी जनसभा को संबोधित किया। सरदार पटेल ने कहा कि कैसे गांधी की प्रार्थनाओं की अवहेलना करके 'ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन खो दिया जिनका प्रेम उनके प्रति सच्चा और गंभीर था'। अब 'गांधी बहत्तर साल के हो चुके है और वे चाहते है कि भारत से ब्रिटिश शासन खत्म हो जाए'। सरदार पटेल ने आगे कहा कि गांधी सोचते हैं कि 'भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निरंतरता किसी दूसरे साम्राज्यवादी देश (जापान) को भी इस देश पर कब्ज़ा करने के लिए उकसाएगी'। ऐसे में 'इन साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के भंवर में युद्ध खिंचता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा'। सरदार पटेल की बंबई जनसभा का पूरा कवरेज गांधी के प्रति निष्ठावान अख़बार बॉम्बे क्रॉनिकल ने किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की पूर्व निर्धारित बैठक 7 अगस्त 1942 को दोपहर 2 बजे केंद्रीय बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में शुरू हुई।

जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी ने लोगों से आग्रह किया कि वे किसी भी सूरत में जापानियों से सहानुभूति न दर्शाएं। उन्होंने कहा की, 'एक ऐसे समय में जब मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू करने जा रहा हूं, मेरे हृदय में

अंग्रेजों के प्रति किसी भी प्रकार की घृणा नहीं हो सकती है'। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी 'जापान के इस तरह से आगे बढ़ते जाने का मतलब चीन का अंत होना और शायद रूस का भी'। गांधी ने कांग्रेसजनों से यह भी अपील की कि 'वे हिंसा का रास्ता न अख्तियार करें और अहिंसा को शर्मिंदा न करें। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें तत्काल भारत से ब्रिटिश राज की समाप्ति की मांग की गई। एक बार भारत आज़ाद हो जाये तो वह युद्ध में मित्र राष्ट्रों का समर्थन करेगा और 'स्वंतत्रता के लिए संयुक्त संघर्ष में साथ मिलकर उथल-पुथल और तकलीफों का सामना करेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने कहा कि 'भारत की स्वतंत्रता अन्य एशियाई राष्ट्रों की विदेशी आधिपत्य से मुक्ति की पूर्वपीठिका और उसका प्रतिक बनेगी'। फ्रांसीसी,डच और अंग्रेजों को अपने-अपने उपनिवेशों से हट जाना चाहिए और 'इसे साफ तौर पर समझ लिया जाना चाहिए कि जो देश जापानी आधिपत्य में हैं उन्हें किसी भी तरह से किसी अन्य औपनिवेशिक शक्ति के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस ने आशा प्रकट की कि ब्रिटेन और अन्य मित्र राष्ट्र भारत की स्वतंत्रता के इस आग्रह पर गौर करेंगे,लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो 'कांग्रेस पूरे देश को साम्राज्यवादी और तानाशाही सरकार के खिलाफ अपनी इच्छा जाहिर करने से नहीं रोकेगी'। ऐसे में स्वतंत्रता के लिए भारत के अखंड अधिकार के समर्थन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 'अहिंसक सिद्धांतों के आधार पर एक व्यापक जनांदोलन की संस्तुति करती है; जो अनिवार्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में की जाएगी'। अखिल भारतीय कांग्रेस के इस प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया और इसका समर्थन सरदार पटेल ने किया। गांधी जब अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रहे थे तब उनके जहन में अपने द्वारा संचालित पूर्वतीय आंदोलनों में अंग्रेजों की सहृदयता की स्मृतियां भी कौंध रही थी। उन्हें लग रहा था कि पूर्व की भांति जब उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था उस समय भी अंग्रेजी शासन ने उन्हें गिरफ्तार करने में एक वर्ष से ज्यादा का समय लगाया था और नमक सत्याग्रह के समय भी समुद्र तट तक जाने दिया गया और कानून तोड़ने दिया गया था तो इस वक्त भी उन्हें तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने यह बात महादेव देसाई से कही थी। लेकिन गांधी जी की धारणा के विपरीत 9 अगस्त 1942 की सुबह 5 बजे उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें पुणे के आगा खान पैलेस में ले जाया गया। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेता नेहरू,सरदार पटेल और मौलाना आजाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अज्ञात स्थल पर ले जाया गया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और इससे जुड़ी संस्थाओं को भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1908 के तहत इस आधार पर गैर-कानूनी घोषित कर दिया कि वे 'सार्वजनिक शांति को खतरा पहुंचा रही हैं'। समूचे देश में कांग्रेस कार्यालय पर ताला लगा दिया गया। आंदोलन से पूर्व ही सरकार की कार्यवाही ने जनता को क्रोधित कर दिया था। बंबई में गांधी की गिरफ्तारी के बाद व्यापक पैमाने पर उपद्रव शुरू हो गए। 'लोगों की भीड़ जिसमें अधिकतर छात्र शामिल थे वे लोकल ट्रेनों में चढ़ गए, उन्होंने शीशे तोड़ डाले,डिब्बों की सीटें और गद्दे तहस नहस कर डाले और अलार्म चैन खींच डाले'। टेलीफोन के तार काट डाले और कार्यालयों में तोड़फोड़ की। नगरपालिका की संपत्ति स्ट्रीट लाइट,लैंप पोस्ट,कूड़ेदान,पानी के पाइप और अन्य वस्तुओं का नष्ट कर दिया गया। हिंदू इलाकों के बाजार बंद थे और यही हाल ज्यादातर स्कूल और कॉलेजों का था। ऐसे ही विरोध प्रदर्शन बंबई प्रेसिडेंसी के अन्य शहरों पूना, अहमदाबाद,सूरत और अहमदनगर में भी हुए। 15 अगस्त को महादेव देसाई की मृत्यु की खबर अहमदाबाद में पहुंची तो पूरे शहर में हड़ताल हो गई। इसके अतिरिक्त भरूच,सूरत और पंचमहल में भी महादेव देसाई की स्मृति में हड़ताल का आयोजन किया गया। गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक 'गांधी सप्ताह' घोषित कर दिया गया था। इस सप्ताह के आरंभ में और अंतिम दिन नगर के विभिन्न भागों में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया जिसे पुलिस बल ने तितर-बितर कर दिया। इस सप्ताह में अधिकांश दुकानें और मिल बंद रहे। इसी के साथ ही 2 अक्टूबर के दिन कई जगहों पर जुलूस निकाला गया। बंगाल में ये विरोध प्रदर्शन सबसे सघन थे।

अगस्त से लेकर नवंबर की शुरुआत तक टेलीग्राफ के तार काटने,पोस्ट ऑफिसों को जलाया गया,दीवारों पर 'आजादी की लड़ाई' लिखे पर्चे चिपकाने, गांव के पटेलों और कर्मचारियों को उनके इस्तीफे न देने की सूरत में उनका घर लूटने की सैकड़ों घटनाएं हुई। कांग्रेस के उग्र आंदोलनकारियों ने देश के अंदरूनी हिस्सों में घूम-घूमकर कहा कि सरकार को कोई कर नहीं दिया जाएगा। उच्च विद्यालय और महाविद्यालयों में हड़ताल का आयोजन किया गया (ऐसे भी कॉलेजों में हड़ताल हुई जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती थीं) नौजवानों ने कॉलेजों की इमारतों पर तिरंगा फहरा दिया। अदालतों का बहिष्कार किया गया। जजों के आधिकारिक परिधान उतार दिए गए और उन्हें 'वंदे मातरम्' कहने के लिए मजबूर किया गया। यह विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे थे इससे ब्रिटिश राज की राजधानी दिल्ली तक अछूती नहीं थी। शहर के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया,लेकिन उनसे थोड़े कम उम्र के नेताओं ने छात्रों को कक्षाओं के बहिष्कार के लिए मना लिया। सरकार की आलोचना वाले पर्चे और न्यूज़लेटर भी बांटे गए। 2 अक्टूबर को एक पर्चा छापा गया जिसमें लिखा हुआ था कि 'आज गांधी जयंती का दिन है। भारत के लोगों से आह्वान किया जाता है कि वे आज उपवास करें और मस्जिदों में,गिरजाघरों में और मंदिरों में हमारे नेता के जीवन और हमारे संघर्ष की सफलता के लिए प्रार्थना करें। सभी दुकानें इस अवसर पर बंद रहें। पूरे शहर में प्रभात फेरी और जुलूस निकाले जाएं'। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के गांधी के आह्वान के समर्थन में हजारों-लाखों लोग उनके समर्थन में आ गए थे। उन्होंने कई तरह से अपना समर्थन व्यक्त किया,जिसे उनके नेता संपूर्ण रूप से स्वीकार भी नहीं कर सकते थे। यह कोई सशस्त्र विद्रोह नहीं था,किसी भी प्रदर्शनकारी ने बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने औपनिवेशिक राज्यतंत्र के प्रतीकों सरकारी कार्यालयों में तोड़-फोड़ की, टेलीफोन, टेलीग्राफ के तारों को काटा गया,रेलवे की संपत्तियों को क्षति पहुंचाने का कार्य,पुलिस थानों को तोड़ा गया। ये सारे के सारे भारत में ब्रिटिश सत्ता को बनाएं रखने में महत्वपूर्ण थे। इन प्रतीकों पर हमला कर प्रदर्शनकारी एक ऐसे राजतंत्र की वैधता पर सवाल उठा रहे थे जिनका शासन गैर-भारतीयों के हाथों में था। गांधी के भारत छोड़ो आह्वान ने विशाल संख्या में भारतीयों की देशभक्ति की भावना को व्यक्त किया।

जिले के सभी संगठनात्मक 30 मण्डल में निकलेगी तिरंगा यात्रा

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर जिला मुख्यालय पर निकलेगा मौन जूलूस

बैतूल। भाजपा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। जिले के सभी संगठनात्मक 30 मंडलो में तिरंगा यात्राएं निकली जाएगी। स्वतन्त्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों एवं शहीद स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। भाजपा जिला मीडिया सेंटर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि गुरूवार को जिले के सभी संगठनात्मक 30 मंडलो में तिरंगा यात्रा को लेकर मंडल बैठके संपन्न हुई। बडोरा, दुनावा और मुलताई नगर मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय

नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमन्त खण्डेलवाल जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ 10 अगस्त से किया जा रहा। इस अभियान में कार्यकर्ता जुट गए है। 10 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे जिले भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। 10 अगस्त से 13 अगस्त तक मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर जिला केंद्र पर मौन जुलूस निकालने के साथ प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में आम जनता और विभिन्न संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। अभियान की सम्पूर्ण जानकारी देते हुए भाजपा जिला महामंत्री एवं तिरंगा यात्रा के जिला संयोजक कमलेश सिंह ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान 3 चरणों मे सम्पन्न होगा। 10 से 13 अगस्त तक सभी संगठनात्मक 30 मण्डलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 12 से 14 अगस्त तक जिले भर में शहीद स्मारकों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुडे महत्वपूर्ण स्थलों के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी घरों, प्रतिष्ठानों पर आम नागरिक और पार्टी कार्यकर्ता तिरंगा लहरायेंगे एवं 15 अगस्त को झंडा फहराने के बाद शाम को सम्मानपूर्वक उतारना भी कार्यकर्ता सुनिश्चित करेंगे। पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व सभी कार्यकर्ता अभियान को ऐतेहासिक रूप से सफल बनाने जुट गए हैं। अभियान के जिला सहसंयोजक भास्कर मागरदे एवं ममता मालवी ने समस्त कार्यकर्ताओ, सामाजिक संगठनों एवं देश भक्त नागरिकों से तिरंगा यात्रा एवं हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की है।

सिकलसेल और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए युवाओं ने दिया 13 यूनिट रक्त

बैतूल। रक्तदान समिति बैतूल बाजार एवं हेल्पिंग मिशन संस्था के सदस्यों द्वारा बैतूल बाजार निवासी पम्मू मयूर राठौर के जन्मदिवस को मानव सेवा के रूप में मनाते हुए जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में 13 यूनिट रक्तदान किया। यह रक्तदान विशेष रूप से

सिकलसेल और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए किया गया। समिति के सदस्य रितिक बारस्कर ने बताया कि पम्मू मयूर राठौर हमेशा बेसहारा और पीड़ितों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यही प्रेरणा युवाओं को हर वर्ष उनके जन्मदिन पर रक्तदान के लिए प्रेरित करती है। रक्तदान के इस अवसर पर ब्लड बैंक अधिकारी डॉ. अंकित सिते, आरएमओ डॉ. रानू वर्मा और राजेश बोरखडे भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि पम्मू मयूर राठौर को उनके सेवा कार्यों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है।

विकासखण्ड स्तर पर आज होगा राष्ट्रीय कला उत्सव 2025 का आयोजन

बैतूल। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानने, उसे पोषित करने और शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2015 से कला उत्सव का आयोजन कर रहा है। जानकारी देते हुए प्रभारी शिक्षक महेश गुंजेले ने बताया कि कला उत्सव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख अवधारणाओं के अनुरूप है, जो समग्र और व्यापक शिक्षा को बढ़ावा देने में इसके महत्व को दर्शाती है। कला उत्सव हेतु इस वर्ष की विषयवस्तु विकसित भारत-वर्ष 2047 के भारत की परिकल्पना है। यह स्कूलों में उत्सव की वह पहल है जो प्रत्येक वर्ष आयोजित हो रही है। भारत सरकार कला उत्सव 2025-26 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मध्यप्रदेश में कला उत्सव की गतिविधियों का आयोजन प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में विभिन्न चरणों में पूर्ण कराया जाना है।

तीसरी फसल से बढ़ी किसानों की आय, आज समर्थन मूल्य में मूँग खरीदी का अंतिम दिन

4118 किसानों से खरीदी मूंग, 102 करोड़ का भुगतान

संजय द्विवेदी, बैतूल। जिले में तीसरी फसल ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती शुरू होने के बाद किसानों की आर्थिक संपन्नता बढ़ी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस साल अब तक जिले के 4118 किसानों ने समर्थन मूल्य पर मूंग बेची है। जिन्हें करीब 102 करोड़ 1 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। अभी खरीदी जारी है और आज खरीदी का अंतिम दिन है। हालांकि किसानों की संख्या को देखते हुए तारीख में बढ़ोत्तरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस साल समर्थन मूल्य पर मूंग-उड़द बेचने के लिए कुल 5198 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिसमें से 4606 किसानों ने स्लार्ट भी बुक किये है। वहीं अभी तक 4118 किसानों से करीब 11749.70 मेट्रिक टन मूंग की खरीदी की जा चुकी है। वहीं उड़द के लिए 45 किसानों ने 53 हेक्टेयर रकबा का पंजीयन कराया था, किन्तु किसानों ने उड़द नहीं बेची। गौरतलब ह कि इस बार जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग 15900 हेक्टेयर रकबे में बोई गई थी और बड़े पैमानें पर मूंग का उत्पादन भी हुआ है।

पिछले साल 3059 किसानों ने बेचा था मूंग- जिले में पिछले साल 3059 किसानों ने समर्थन मूल्य में मूंग बेचा था। हालांकि पिछले साल 3697 किसानों ने पंजीयन कराया था, किन्तु 638 किसानों ने मूंग नहीं बेचा। वहीं 3059 किसानों से 6630 एमटी (मेट्रिक टन) मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी हुई थी। जबकि इस साल 5153 किसानों ने 13396 हेक्टेयर मूंग के लिए पंजीयन कराया है। वहीं उड़द के लिए 45 किसानों ने पंजीयन किया था। वहीं स्लॉट बुकिंग की बात करें तो 4606 किसानों ने स्लॉट बुक कराए हैं। इनमें से 4118 किसानों ने समर्थन मूल्य पर मूंग बेच दी है। बचे किसान भी लगातार खरीदी केन्द्र पहुंचकर मूंग बेच रहे है।

102 करोड़ का भुगतान, 63 करोड़ के ईपीओ जारी - समर्थन मूल्य में मूंग बेचने वाले किसानों को भुगतान किये जाने की प्रक्रिया भी जारी है। विभाग द्वारा अभी तक 102 करोड़ 1 लाख रूपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। वहीं 63 करोड़ के ईपीओ जनरेट हो चुके है। अधिकारियों को कहना है कि जैसे-जैसे डब्ल्यूएचआर बनते जा रही है, वैसे-वैसे किसानों का भुगतान हो रहा है। अभी साढ़े चार सौ से पांच सौ किसानों का भुगतान होना बाकी है। रोजाना जो खरीदी हो रही है, शाम को ईपीओ जारी किये जा रहे है।

करीब 11060 मेट्रिक टन मूंग का परिवहन

विभाग द्वारा अनुमानित कुल लक्ष्य से अधिक मूंग की खरीदी की गई है। बताया जा रहा है कि अनुमानित कुल लक्ष्य 10000 था, जबकि विभाग ने अभी तक 11749.70 मेट्रिक टन मूंग की खरीदी कर ली है। वहीं खरीदी केन्द्रों से 11060.25 मेट्रिक टन मूंग का परिवहन भी किया जा चुका है। वहीं खरीदी केन्द्रों पर 357.35 मेट्रिक टन जो मूंग परिवहन के लिए रखी है, उसका भी निरंतर परिवहन कार्य जारी है। बता दे कि कृषि विभाग द्वारा मूंग-उड़द खरीदी के पंजीयन के लिए जिले में 34 पंजीयन केन्द्र बनाये थे, वहीं 22 खरीदी केन्द्रों पर मूंग की खरीदी की जा रही है।

इनका कहना -

जिले के 5198 किसानों ने मूंग-उड़द बेचने के लिए पंजीयन कराया था, जिसमें से 4606 किसानों ने स्लार्ट बुक किए है, वहीं अभी तक 4118 किसानों से मूंग खरीदी गई है।

- डॉ. आनंद बडोनिया,
उप संचालक, कृषि विभाग, बैतूल

किसानों को करीब 102 करोड़ 1 लाख का भुगतान हो चुका है। वहीं 63 करोड़ के ईपीओ जनरेट किये गये है। जैसे-जैसे-जैसे डब्ल्यूएचआर बनते जा रहे है, वैसे-वैसे किसानों का भुगतान हो रहा है।

- राधेश्याम निगम,
जिला विपणन अधिकारी, बैतूल

भौंरा के निजी स्कूल में बोलेरो वाहन से बच्चों का परिवहन

बैतूल/भौंरा। भौंरा नगर में स्थित लिटिल एंजेल प्राइवेट स्कूल में स्कूली बच्चों के परिवहन को लेकर एक मामला सामने आया है, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी से बिना कमर्शियल परमिट के बच्चों को लाने-ले जाने की बात कही जा रही है। इस पर जहां कुछ अभिभावकों ने चिंता जताई है, वहीं स्कूल प्रबंधन ने इसे अस्थायी व्यवस्था बताया है। यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन, परिवहन विभाग और पालकों के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों के लाने-ले जाने में जिस बोलेरो वाहन का उपयोग किया जा रहा है, वह निजी उपयोग के लिए पंजीकृत है और उस पर सफेद नंबर प्लेट है। वाहन पर स्कूल वेन अंकित नहीं है और वाणिज्यिक परमिट भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा सुरक्षा सुविधाएं जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर, सीट बेल्ट आदि भी वाहन में मौजूद नहीं बताए जा रहे हैं। परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा 2017 में जारी दिशानिर्देशों और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु केवल कमर्शियल परमिट वाले पीली नंबर प्लेट वाहनों का उपयोग किया जा सकता है। वाहन पर स्कूल वेन लिखा होना चाहिए। चालक के पास व्यावसायिक लाइसेंस और कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। वाहन में सुरक्षा उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा किट अनिवार्य हैं।

अभिभावकों की चिंता

बच्चों के पालकों ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि हम बच्चों को यह मानकर स्कूल भेजते हैं कि उनकी सुरक्षा का समुचित ध्यान रखा जाएगा, लेकिन निजी वाहन का इस प्रकार उपयोग नियमों के विरुद्ध है। यदि कोई दुर्घटना होती है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? कुछ पालकों ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों की कमी को देखते हुए अस्थायी व्यवस्था समझ में आती है, लेकिन इससे सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। स्कूल प्रिंसिपल मानव शुक्ला ने बताया कि हम बच्चों की संख्या कम होने और संसाधनों की सीमितता के कारण अस्थायी रूप से निजी बोलेरो वाहन का उपयोग कर रहे हैं। हम किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहते और बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यदि विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, तो हम उनका पालन करेंगे।

इनका कहना है -

बिना परमिट स्कूली बच्चों का परिवहन मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है और वाहन की जांच के निर्देश दिए हैं। नियमों के विरुद्ध पाए जाने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तथा स्कूल प्रबंधन से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

-अनुराग शुक्ला,
जिला परिवहन अधिकारी, बैतूल

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के क्रियान्वयन का प्रशिक्षण आयोजित

आवास क्रय या निर्माण के लिए होम लोन पर मिलेगी 1.8 लाख की ब्याज सब्सिडी

बैतूल। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत 01 सितंबर 2024 को या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए होम लोन पर ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी के पात्र लाभार्थियों को आवासों की खरीद/पुनर्खरीद/ निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ दिए जाने के सम्बन्ध में गुरुवार को कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की उपस्थित में कलेक्टर कार्यालय में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने प्रशिक्षण में कहा कि केंद्र की यह बहुत अच्छी योजना हैं। इस योजना से पात्रों को लाभान्वित किए जाने के लिए अगस्त माह को प्रधानमंत्री आवास माह भी घोषित किया गया है। सभी सम्बन्धित विभाग पूरी गंभीरता से योजना का क्रियान्वयन कराएं। जिसमें सभी बैंकों के प्रतिनिधियों की विशेष भूमिका रहेगी। अग्रणी बैंक प्रबंधक इस स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लीडरशिप लेंगे। सतत बैंकवार इस स्कीम के तहत होम लोन स्वीकृति कि बैंकवार समीक्षा की जाएं। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में 11 अगस्त तक अनिवार्य रूप से ब्लॉक लेवल बीएलसीसी की बैठक आयोजित करें। इसके साथ ही निकायवार कैंप भी आयोजित कराए, जिसमें सभी बैंक भी सक्रिय सहभागिता करें। निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा में हासिल किया जाए। सभी बैंक, सीएमओ यह प्रयास करें कि आने वाले शुभ मुहूर्तों पर हितग्राही योजना के तहत लाभान्वित हो गृह प्रवेश कर सक सकेंगे। योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के परिवार के लिए जिनकी वार्षिक आय क्रमशः 3 लाख ,6 लाख और 9 लाख है, इस घटक का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। गृह ऋण की अधिकतम राशि 25 लाख रुपए और आवास का अधिकतम मूल्य 35 लाख रुपए तक हो सकेगा। इन हितग्राहियों को आवास क्रय या निर्माण के लिए गृह ऋण पर अधिकतम 1.8 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी प्राप्त हो सकेगी। योजना के तहत ईडब्ल्यूएस एलआईजी एमआईजी लाभार्थी की पहचान करने के लिए आवेदक आय प्रमाण के रूप में प्रमाणित पत्र एफिडेविट प्रस्तुत करेगा। आयोजित बैठक में पीओ डूडा एवं सीएमओ बैतूल सतीश मटसेनिया सहित समस्त एसडीएम, सीएमओ, अग्रणी बैंक प्रबंधक, बैंकर्स सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।

योजना के तहत पात्रता- आवेदक का भारत में कहीं भी स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां सम्मिलित होंगी, अविवाहित बेटे/बेटियों को पृथक से लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।जिन आवेदकों द्वारा शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 20 वर्षों में किसी भी आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया है, वे पी.एम.ए.वाई.-यू 2.0 अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

आवश्यक दस्तावेज/जानकारी - आवेदक तथा आवेदक के परिवार के सदस्यों (माता, पिता, पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र/पुत्री) के आधार क्रमांक, आवेदक का पीएएन क्रमांक, आवेदक के परिवार की आय का सेल्फ डिक्लेरेशन, आवेदन के लिए योजना के दिशा निर्देश के एनेक्सचर-3 अनुसार निर्धारित सर्वेक्षण फॉर्म की सम्पूर्ण जानकारी। आईएसएस घटक के लिए निर्धारित एनेक्सचर-2C अनुसार सेल्फ-अंडरटेकिंग की यूनिफाइड वेब पोर्टल पर स्वीकृति आवश्यक होगी। पात्र हितग्राही भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

40 लाख की लागत से बना इंडोर बैडमिंटन हाल बदहाल

टूट रहा फर्स, जर्जर हुई नेट, चिथड़ों में तब्दील हुई मेट

बैतूल/ मुलताई। नगर पालिका मुलताई लाखों रुपए खर्च कर विकास कार्य कराती है और फिर उसे भूल जाती है नतीजा चंद समय में ही विकास गायब हो जाता है। इन विकास कार्यों के रखरखाव के प्रयास क्यों नहीं होते तो इसका उत्तर है नगर पालिका का सरोकार निर्माण के भुगतान तक ही सीमित होता है और इसका नतीजा है कि मुलताई नगर में अनेक भवन उपयोग के बगैर ही खंडहरों में बदल गए और हाल ही में इसका दूसरा उदाहरण नगर का एकमात्र इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम होने जा रहा है। रखरखाव एवं मेंटेनेंस के अभाव में 40 लाख 40 हजार रुपए की लागत से बना बैडमिंटन हॉल आज बदहाली का शिकार है। महज कुछ सालों में ही हॉल की हालत ऐसी हो गई है कि स्टेडियम में खिलाडियों का खेलना कठिन हो रहा है। अनेक खिलाड़ी अपने पैसों से छोटी-मोटी मरम्मत करा कर इस बैडमिंटन हाल को खेलने लायक बनाते हैं खिलाड़ी बताते हैं कि जिस फ्लोरिंग (मैट/कोर्ट की सतह) पर खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, वह बुरी तरह फट और उखड़ चुकी है। खिलाडियों का कहना है कि यह सतह अब खेलने लायक नहीं बची है। मगर कोई देखरेख या मरम्मत की व्यवस्था नहीं है। मजबूरन बच्चे और युवा खिलाड़ी टेप लगाकर जगह-जगह उसे जोडने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अभ्यास जारी रह सके। नगर के एसडीओपी बंगले के पास बने इस हॉल का निर्माण नगर पालिका अध्यक्ष हेमंत शर्मा के कार्यकाल में हुआ था तब इसे नगर के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था किंतु निर्माण प्रारंभ हुआ तो गुणवत्ता पर सवाल भी उठे किंतु हमेशा की तरह ना तो तब कुछ हो पाया था और ना अब कुछ हो पाएगा और नगर की एक और खेल उपलब्धि समाप्त हो जाएगी।

इंडोर हाल में लगा गंदगी का अंबार नहीं होती सफाई

बैडमिंटन हॉल में जगह-जगह से निकल रहा प्लास्टर, नीचे टूट रहा फर्स और चिथडो में तब्दील हो गई मेट की बात तो दूर है नगर पालिका हॉल के भीतर फैली गंदगी हटाकर सफाई करना तक आवश्यक नहीं समझती जिसको लेकर खिलाडियों में रोष है। लाखों रुपए की लागत से बने इस हॉल को नियमित देखरेख नहीं मिलने के कारण यह बर्बादी की कगार पर है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह हॉल भी एक और सरकारी उजड़ा स्मारक बनकर रह जाएगा।

इनका कहना है-

इससे संबंध में अभी कोई शिकायत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी खिलाडियों से चर्चा कर आवश्यक सुधार कार्य जाएंगे।

- महेश शर्मा
उपयंत्री नगर पालिका मुलताई

आयुष्मान में हमीदिया के अटके 6.6 करोड़ रुपए पास

नई व्यवस्था लागू, मरीजों का 24 घंटे में बनेगा आयुष्मान कार्ड, डॉक्टर को मिलेगा इंसेंटिव

भोपाल (नप्र)। हमीदिया अस्पताल में आयुष्मान योजना से जुड़ी समस्याओं का बड़ा समाधान हुआ है। नई व्यवस्था लागू होने से दो साल से अटके 6.6 करोड़ रुपए के बिल पास हो गए हैं। साथ ही अब मरीजों के आयुष्मान कार्ड 24 घंटे में तैयार होंगे और डॉक्टरों को तय इंसेंटिव भी मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान मरीजों का कन्वर्जन रेट 35 प्रतिशत (1 जुलाई) से बढ़कर 60 प्रतिशत (1 अगस्त) तक पहुंच गया है।

यह बदलाव पुराने खराब ट्रैक रिकॉर्ड को सुधराने के लिए किया गया है। दरअसल, मध्यप्रदेश की राजधानी में स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) आयुष्मान योजना के तहत इलाज मुहैया कराने में पिछड़ा हुआ था। जीएमसी के हमीदिया अस्पताल में 1 जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे मरीज जो आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र थे लेकिन उनके पास कार्ड नहीं था, उनका कन्वर्जन रेट सिर्फ 35 प्रतिशत था।

यानी 100 मरीजों में से केवल 35 का कार्ड ही अस्पताल प्रबंधन बना पा रहा था। यही नहीं, आयुष्मान पोर्टल पर गलत या अधूरी जानकारी भरने के कारण

पिछले दो साल में 6.62 करोड़ रुपए के बिल भी अटके थे। इस स्थिति को देखते हुए, आयुष्मान योजना की जिम्मेदारी हमीदिया अस्पताल प्रबंधन से लेकर जीएमसी प्रबंधन ने अपने पास ले ली है।

5 साल से डॉक्टरों को नहीं मिला इंसेंटिव- हमीदिया अस्पताल में पिछले 5 साल से आयुष्मान योजना का संचालन चुनौतीपूर्ण था। कम कन्वर्जन रेट, इलाज के बाद पोर्टल पर गलत जानकारी डालने से बिल अटकना और वेंडर का बकाया बढ़ने पर जरूरी सामान की सप्लाई रुक जाना बड़ी समस्या थी। पहले आयुष्मान योजना से मिलने वाली राशि से वेंडरों का भुगतान किया जाता था, जिससे डॉक्टरों को इंसेंटिव नहीं मिल पा रहा था।

अब मिलेगा डॉक्टरों को इंसेंटिव- जीएमसी डीन डॉ. कविता एन सिंह ने बताया कि अब डॉक्टरों को आयुष्मान मरीज का इलाज करने पर तय इंसेंटिव मिलेगा। हमने वेंडरों के पुराने बिल चुका दिए हैं। अब आने वाली राशि से डॉक्टरों को इंसेंटिव और मरीजों की सुविधाओं पर खर्च होगा।

24 घंटे नो पेंडेंसी रूल लागू- जीएमसी में 24 घंटे नो पेंडेंसी रूल लागू किया गया है। इसके तहत 15 नए आयुष्मान मित्र अपॉइन्ट किए गए हैं। हर क्लीनिकल विभाग में एक आयुष्मान कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है। ये विभागाध्यक्ष के साथ मिलकर सभी कार्य 24 घंटे में पूरे करेंगे। पेंडिंग कार्य की जानकारी रजिस्टर में दर्ज होगी और नोडल ऑफिसर द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। इधर, 15 अगस्त से आयुष्मान मित्र एप्रन पहनेंगे, जिस पर आयुष्मान मित्र का लोगो होगा ताकि मरीज और परिजन उन्हें आसानी से पहचान सकें। इसके अलावा कार्ड बनाने के लिए 13 नई बायोमैट्रिक मशीनें भी खरीदी गई हैं।

बालाघाट में बाघ शिकार मामले की एनटीसीए से शिकायत

आरोप- शिकार में वनकर्मियों की मिलीभगत, डीएफओ के विरुद्ध हाईलेवल जांच हो

भोपाल (नप्र)। प्रदेश के बालाघाट जिले में एक हफ्ते पहले बाघ के शिकार और इसमें वन कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मिलीभगत का मामला अब एनटीसीए तक पहुंच गया है। मामले की हाईलेवल जांच के साथ डीएफओ की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है। वन बल प्रमुख से कहा गया है कि सही जांच हुई तो शिकार के और भी मामले सामने आ सकते हैं। एनटीसीए (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) को शिकायत करते हुए वाइल्ड लाइफ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अजय दुबे ने कहा है कि कान्हा- पेंच कॉरिडोर में स्थित बालाघाट साउथ के सोनवानी वन क्षेत्र के कंपार्टमेंट 443 में बाघ के शिकार के लिए अज्ञात दोषियों के साथ मृत बाघ के शरीर को नष्ट करने में वन कर्मियों का शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि इस मामले में विजय अम्बाड़े पीसीसीएफ को 2 अगस्त 2025 की दोपहर में पूरे मामले की जानकारी देने के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ। दुबे ने कहा कि प्रस्तावित सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व में 60 से अधिक बाघों की उपस्थिति है लेकिन बालाघाट साउथ डिवीजन के डीएफओ अधर गुप्ता न ऑफिस में रहते हैं न फील्ड पर भ्रमण करते हैं। बाघ के शिकार की सूचना स्थानीय लोगों में 27 जुलाई 2025 से वायरल हो गई थी, लेकिन सीसीएफ से वन रक्षक तक के वन अफसर, कर्मचारी निष्क्रिय रहे।

संक्षिप्त समाचार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन

विदिशा (निप्र)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देशन एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जाकिर हुसैन के मार्गदर्शन में नालसा (नशीली दवाओं के खतरे के उन्मूलन के लिये पीडितो के लिये कानूनी सेवाऐं) योजना 2015 के अतंर्गत निबंध प्रतियोगिता का आयोजन नारायणा ई-टेक्नो स्कूल एवं स्प्रिंग फील्ड स्कूल विदिशा में किया गया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले छात्रो का चयन किया गया। ई- नारायणा स्कूल के शुभम बघेल कक्षा-8, कु. निशी दांगी कक्षा-6 एवं कु. सानवी त्रिपाठी कक्षा-6 को निबंध प्रतियोगिता मे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयन किया गया एवं स्प्रिंग फील्ड स्कूल के अरिन्धम अर्पण गुप्ता कक्षा-8, आदित्यसिंह परमार कक्षा-6 एवं जतिन रघुवंशी कक्षा-9 को निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा श्री जाकिर हुसैन द्वारा चयनित बच्चो को पुरूस्कृत करने हेतु सर्टीफिकेट व ट्रॉफी वितरित कराए गये। स्कूलों के प्रधान अध्यापकों ने विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा का आभार व्यक्त किया।

जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने कन्या शिक्षा परिसर में छात्राओं से बंधवाई राखी

सीहोर (निप्र)। सीहोर स्थित कन्या शिक्षा परिसर में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री डॉ शाह ने छात्राओं से राखी बंधवाई। इस अवसर पर मंत्री डॉ. शाह ने छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए कहा बेटियों को अधिक से अधिक शिक्षित होकर अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। सरकार बेटियों की शिक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। उन्होंने स्कूल में संचालित व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में छात्राओं ने जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक श्री अरविंद कुशवाहा, प्रबंधक श्री सत्येंदर शर्मा, स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकों को भी राखियां बांधी।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुलताई की दुकानों का किया औचक निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की सघन जांच एवं नमूने लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन श्री शैलेंद्र बड़ोनिया के मार्गदर्शन में मंगलवार को खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले मुलताई के प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई तथा खाद्य कारोबार कर्ताओं को प्रतिष्ठान में साफ सफाई रखने की हिदायत दी गई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पुरुषोत्तम भंडारिया द्वारा मुलताई स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जाम दूध के 2, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति दुनावा से दुध के 2, विजय स्वीट्स दुनावा से मिठाई का 1 एवं बेसन का 1, बीकानेर मिष्ठान भंडार फवारा चौक मुलताई से काजू कतली का 1 व खोवा का 1 इस प्रकार कुल 08 नमूने लिए गए। लिए गए सैंपल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

गोराखाल वाटरफॉल पर सुरक्षा के दृष्टिगत रैलिंग बढ़ाई जाए

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की अनदेखी करने वालों के प्रति कलेक्टर का सख्त रूख

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने जिले के वनक्षेत्र गोराखाल में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण वाटरफॉल में पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत 20 मीटर रैलिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा है कि यहां पर्यावरण प्रभावित न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए एवं कचरे के संग्रहण के लिये पर्याप्त संख्या में डस्टबिन रखे जाएं।

मंगलवार को आयोजित समयावधि अंकित पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने जिले में यूरिया वितरण सुव्यवस्थित तरीके से करने के अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होने कहा कि सहकारी समितियों में अधिक से अधिक यूरिया उपलब्ध कराया जाए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की एल-वन स्तर पर अनदेखी करने वाले अधिकारियों के प्रति कलेक्टर का सख्त रूख रहा। महिला एवं बाल विकास में दर्ज शिकायतें अनअटेंडेड पाये जाने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी एवं तीनों बाल विकास परियोजना अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। इसी तरह जिला पंचायत में अनअटेंडेड शिकायतें पाये जाने पर जिम्मेदार कर्मचारी का एक सप्ताह का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले बाल विकास परियोजना अधिकारियों का भी एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये। बैठक में नवजात शिशुओं के जन्म प्रमाण-पत्र उनके अभिभावकों को सहूलियत से प्रदान करने के निर्देश दिये गये। जिले के मुख्य मार्गों पर विचरण कर रहे निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में शिफ्ट किये जाने पर भी कलेक्टर द्वारा जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि जिले में अवैध शराब विक्रय को मुहिम चलाकर रोका जाए। साथ ही इस तरह के कार्यों में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण लंबित न रहें

बैठक में कहा गया कि सभी विभाग उनके अधीन सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण दो माह में पूर्ण कर जिला पेंशन अधिकारी को प्रेषित करें। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि खरीफ फसलों की गिरदावरी का कार्य प्रारम्भ किया जाए। उद्यानिकी एवं श्री अन्न फसलों की गिरदावरी में पटवारी एवं विभाग के आंकड़ों में फर्क न आए। कलेक्टर ने कहा कि अवैध कालोनियों के निकट कार्यवाही में कोई रियायत न बरती जाए।

अब दो मंजिला होंगे, स्कूल आंगनवाड़ी भवन

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शासकीय स्कूल अथवा आंगनवाड़ी परिसरों में बच्चों को पर्याप्त खेलकूद के स्थान सुरक्षित रखने के दृष्टिगत अब नये स्कूल व आंगनवाड़ी भवनों का डिजाइन दो मंजिला भवन बनाया जाएगा एवं यह भवन दो तल वाले निर्मित किये जायेंगे।

कलेक्ट्रेट भवन की मरम्मत एवं रंगरोगन होगा

संयुक्त कार्यालय भवन (कलेक्ट्रेट) में आवश्यक मरम्मत कराई जाकर नये सिरे से रंग रोगन कराया जाएगा। कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को भवन की छत की वाटर प्रूफिंग कराने, खिड़कियों में कांच एवं मच्छर जाली लगाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि प्रसाधन कक्षों में नलों इत्यादि की मरम्मत कराई जाए। साथ ही भवन की अन्य आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित की जाए।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं से हितग्राहियों को जोड़ने लगेंगे शिविर : बैठक में कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को जोड़ने के लिये जिले में शिविर आयोजित किये जायें। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सविता झानिया, संयुक्त कलेक्टर सुश्री रजनी वर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा मावा के नमूने लिये

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा आगामी त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जिले में निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। आज मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विदिशा के रामजी मिठाईवाला राजीव नगर, गुरुनानक स्टोर तिलक चैक, भावसार स्वीट्स पीतल मिल का निरीक्षण किया गया। तिलक चैक गुरुनानक स्टोर से मावा, पनीर, सोन पपड़ी, गुलाब जामुन मिक्स, नमकीन मिक्सचर तथा भावसार स्वीट्स पीतलमिल चैराहा से मावा, मिल्क केक, मगज के लड्डू, हल्दीराम रसगुल्ला आदि के नमूने लिए गए तथा सभी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी प्रतिष्ठान संचिलक मिलावटी खाद्य सामग्री का निर्माण व विक्रय ना करें, खाद्य सामग्री निर्माण स्थल की निरंतर साफ-सफाई करें, खाद्य पदार्थ निर्माणकर्ता एप्रोन, हेडकेप, पहने तथा न्यूज पेपर में खाद्य सामग्री ना दें, समोसा, कचैरी आदि खाद्य सामग्री दोने में दें।

हितग्राहियों को जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिले: प्रभारी मंत्री श्री पंवार

रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज स्थित आजीविका भवन में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह पंवार की अध्यक्षता में विकास और निर्माण कार्य तथा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

जिसमें प्रभारी मंत्री श्री पंवार द्वारा भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कार्य समय पर पूर्ण कराए जाएं। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रत्येक स्तर पर मॉनीटरिंग की जाए जिससे कि प्रत्येक पात्र और जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं

का लाभ पहुंचे। बैठक में भोजपुर विधायक श्री सुरेन्द्र पटवा ने भी क्षेत्र में चल रहे विकास और निर्माण कार्यों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा तथा जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया द्वारा भोजपुर विधानसभा सहित जिले में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया।

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमार पाण्डे, डीएफओ श्री हेमंत रायकवार सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी और अनुभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अत्याधुनिक रेल कोच फैक्ट्री के शिलान्यास कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण जिले के प्रभारी मंत्री श्री पंवार तथा भोजपुर विधायक श्री पटवा द्वारा आगामी 10 अगस्त को केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित अत्याधुनिक रेल कोच फैक्ट्री के शिलान्यास कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह आगामी 10 अगस्त को 1800 करोड़ रूपए के निवेश से प्रारंभ होने वाली रेल कोच निर्माण इकाई का शिलान्यास करेंगे। इस इकाई के फलस्वरूप लगभग 1575 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा।

रेत, गिट्टी, मुरूम का अवैध परिवहन करते 2 डम्पर और 3 ट्रैक्टर-ट्राली जप्त

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत खनिज विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 5 अगस्त को मुलताई तहसील अन्तर्गत वाहन डंपर क्रमांक एमएच 49 एटी 6006 को खनिज मुरूम का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जप्त कर पुलिस चौकी प्रभात पट्टन की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। इसी प्रकार निरीक्षण के दौरान 2 अगस्त को तहसील बैतूल, चिचोली व आठनेर क्षेत्र में डंपर क्रमांक एमपी 48 एच 3569, ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 48 जेडबी 8095, ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 48 ए 5552 एवं ट्रेक्टर-ट्राली बिना नंबर को गौण खनिजों के अवैध परिवहन एवं ओवरलोड परिवहन करते पाए जाने पर जप्त कर समीपस्थ पुलिस

थानों की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। उक्त वाहनों के वाहन चालकों, वाहन मालिकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर मध्यप्रदेश अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण नियम 2022 के प्रावधानों के तहत प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर सतत निगरानी रखते हुए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

हरदा के खाद्य प्रतिष्ठानों से मिठाईयों के नमूने लिये

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग के दल ने मंगलवार को हरदा के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर मिठाईयों के सैम्पल लिये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कांबले ने बताया कि निरीक्षण के दौरान हरदा के श्री राजस्थान मिष्ठान से केसर बर्फी और मावा बर्फी, बादर स्वीट हरदा से मलाई बर्फी तथा न्यू पुरोहित स्वीट हरदा से पेड़ा और मिल्क केक के सैंपल लिये गये।

एक पेड़ मां के नाम अभियान तहत पौध-रोपण

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हर रोज पौधरोपण कार्य किया जा रहा है। इसी कडी के तहत मंगलवार को विदिशा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कागपुर में आज एक पेड़ मां के नाम अभियान तहत पौध-रोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बासौदा विधायक श्री हरिसिंह रघुवंशी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह बघेल, पूर्व उपाध्यक्ष वन विकास निगम श्री राममोहन बघेल, कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ समेत अन्य जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने सांस्कृतिक भवन कागपुर में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में सहभागिता निभाई है। यहां पीपल आम अशोक सहित अन्य प्रजातियों के पौधे लगाएं गए है।

रंगई बेरखेडी :

ग्राम रंगई बेरखेडी में भी पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था यहां सहकारिता विभाग के माध्यम से आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने जामुन का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ, कॉ-आपरेटिव बैंक के सीईओ, सहकारिता विभाग के उपायुक्त, उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक समेत अन्य विभागो के अधिकारियों ने पौधरोपण कार्यक्रम में सहभागिता निभाई है। बेतवा नदी के समीप स्थित रंगई बेरखेडी में सहकारिता विभाग के माध्यम से एक हजार पौधे रोपित करने का लक्ष्य तय किया गया है। उक्त अभियान के तहत हर रोज पौधरोपण कार्यक्रम हेतु व्यवस्थाएं क्रियान्वित की जा रही है।

सिलवानी में जप्त की गई 75 हजार रू मूल्य की सागौन ईमारती वनोपज

रायसेन (निप्र)। जिले में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार तथा वन मण्डल अधिकारी सामान्य रायसेन श्रीमति प्रतिभा शुक्ला के निर्देशन में वन अमले द्वारा वनोपज की अवैध कटाई और परिवहन करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई सिलवानी में जप्त की गई 75 हजार रू मूल्य की सागौन ईमारती वनोपज रायसेन, 05 अगस्त 2025 जिले में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार तथा वन मण्डल अधिकारी सामान्य रायसेन श्रीमति प्रतिभा शुक्ला के निर्देशन में वन अमले द्वारा वनोपज की अवैध कटाई और परिवहन करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

वन परिक्षेत्र पश्चिम सिलवानी सामान्य के वन परिक्षेत्र अधिकारी महेन्द्र कुमार पालेचा ने वन अमले के साथ मुखबिरी के आधार पर मुजाहिद हुसैन आत्मज जाहिद हुसैन निवासी वार्ड 6 पड़ान सिलवानी एवं तलैया मोहल्ला दो स्थानों पर दबिश दी। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में सागौन ईमारती चिरान एवं गोल 110 नग, 0.784 घन

मीटर जप्त की गई जिसका बाजार मूल्य लगभग 75000 है। आरोपी मुजाहिद हुसैन आत्मज जाहिद हुसैन निवासी वार्ड 6 पड़ान सिलवानी के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये उसके विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 47374/8 एवं 47356/19 दिनांक 05 अगस्त 2025 को दर्ज किया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

राइट क्लिक

एक रूद्राक्ष से भी कम है अंधश्रद्धा में पगे प्राणों का मोल..!

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।

संपर्क-

9893699939

ajaybokil@gmail.com

म प्र के सीहोर जिले में भोपाल-इंदौर हाई वे पर स्थित कुबेरेश्वर धाम में इस बार भी मुफ्त रूद्राक्ष पाने की अफरा-तफरी में अब तक 7 लोगों ने जानें गंवां दीं। यह स्थिति तब है कि जब कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा किसी दूसरी जगह सावन में कांवड़ यात्रा निकलवा रहे हैं, भक्तों की भीड़ देखकर नाच रहे हैं। भगदड़ में मरने वालों का उन्हें रत्ती भर भी मलाल नहीं। जीवन का क्या, वो नश्वर है। और गरीब भक्तों की तो इतनी भी हैसियत नहीं कि कोई उनकी मौत पर दो आंसू बहाकर इस महोत्सव पर कोई दाग लगाए। पंडितजी से इन असमय मौतों के बारे में पूछा गया तो वही रटा रटाया जवाब मिला-'क्या करें, उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ गई। पिछले साल 3 लाख आए थे, इस दफा और ज्यादा आए होंगे। घंटों हाई वे जाम हुआ सो अलग। यात्री परेशान हुए, ट्रैफिक संभालते प्रशासन का दम निकल गया। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आस्था की राह में सब सहना पड़ता है। भौतिक कष्टों से मुक्ति ही सच्चा मोक्ष है। वो इस बार पांच लोगों को मिला। जिनके स्वजन रूद्राक्ष लूटने की आस में मारे गए, उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है, क्योंकि उनको यहां पूर्व में भी मचे भगदड़ की कहानी किसी ने सुनाई नहीं होगी और सुनाई भी होगी तो उन्होंने इसे झुठलाया होगा। क्योंकि पंडितजी की महिमा अपरंपार है। ऐहिक लीलाओं से परे है।

वैसे भी कुबरेश्वेर धाम में बीते चार सालों में 8 श्रद्धालु अकारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका शायद ही किसी को मलाल हो। धार्मिक आस्था अपनी जगह है, मानव जीवन में उसका महत्व भी है, लेकिन जब आस्था अपना विवेक गिरवी रख दे तो वह शुद्ध अंधभक्ति में तब्दील हो जाती है। तब व्यक्ति अपने मोक्ष, सांसारिक कष्टों से मुक्ति और कथित रूप से आध्यात्मिक जगत में रममाण हो जाने के लोभ में उचित-अनुचित, तार्किक-अतार्किक का भेद भी भुला बैठता है और खुद एक अंधी भीड़ का हिस्सा बन जाता है। वह यह भी बिसरा देता है कि ईश्वर ने यह अनमोल जनम महज रूद्राक्ष की राह में गंवाने के लिए नहीं दिया है। हालांकि इस बार फर्क यह दिका कि पं.प्रदीप मिश्रा और उनकी भक्त मंडली द्वारा हर साल रूद्राक्ष बांटने के नाम पर जुटाई जाने वाली बेतहाशा भीड़ और अफरा-तफरी को रोकने राजनीतिक हल्कों से रूद्राक्ष वितरण पर रोक लगाने तथा बाबा के जांच कराने की मांग उठने लगी है। वोटों का भोग लगाने की जगह मानवीय त्रासदी की चुभन महसूस की जाने लगी है। राज्य के मंत्री करणसिंह वर्मा ने आम जनता के दबाव में घटना की न्यायिक जांच का ऐलान कर जरूरी कार्रवाई से पल्ला झाड़ किया है। यानी कब जांच होगी और कब कोई दोषी पाया जाएगा। जिम्मेदारों पर तत्काल और सीधी कार्रवाई से बचने का कानूनी बहाना है। जो मौतें सबके सामने हुईं, जो मौतें सबके कारण हुईं, जिनका पूरी दुनिया को पता है, उस प्रकरण में लंबी जांच किस बात की? इस साल भगदड़ में जिन पांच लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, क्या उनके प्राणों की कीमत एक रूद्राक्ष के मोल से भी कम है? न्यायिक जांच बरसों चलेगी। नतीजा एक रूद्राक्ष के बराबर भी नहीं निकलेगा। पंडितजी बेखौफ भीड़ जुटाते रहेंगे। हाई वे पर जाम लगता रहेगा। और प्रशासन बेबस होकर यह सब देखता रहेगा, क्योंकि आस्था की चादर पर सियासी सलमे की झालर टंकी है।

वैसे सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में यह कोई नया नजारा नहीं है। बताया जाता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा वहां भक्तों को प्रसाद की तरह हजारों रूद्राक्ष बांटते हैं। भक्तों की मान्यता है कि इस रूद्राक्ष को रात में पानी में भिगोकर वो पानी पीने से सभी तरह के रोग आदि से मुक्ति मिल जाती है। काश, ऐसा होता! तो देश में इतने डॉक्टरों, दवाखानों पर ताले पड़ चुके होते। मेडिकल कॉलेजों में केवल रूद्राक्ष ट्रीटमेंट पढ़ाकर मुक्ति पाई जाती। देश में सिर्फ रूद्राक्ष की खेती और वितरण होता। इस हकीकत को जानते हुए भी अगर लोग रूद्राक्ष अथवा पंडितजी का आशीर्वाद पाने के लिए टूटे पड़ रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि अब अपने दिमाग से कोई सोचना नहीं चाहता। आस्था की चाशनी में मंद हो चुकी बुद्धि को सोशल मीडिया के सुनियोजित प्रचार ने पूरी तरह कुंद कर दिया है। भक्तों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि असली रूद्राक्ष काफी महंगा मिलता है। उसे रेवड़ी तरह बांटने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अफवाह यह है कि आश्रम में बंटने वाला रूद्राक्ष 'अभिमंत्रित' है और सब बुराइयों की एक ठो दवा है। आज तक किसी ने यह भी नहीं पूछा कि जो रूद्राक्ष बांटे जा रहे हैं, वो असली है भी या नहीं, अभिमंत्रित है भी या नहीं? कहां से आ रहे हैं? आजकल नकली रूद्राक्ष का कारोबार भी खूब फलफूल रहा है। ये प्लास्टिक या रेजीन से बनते हैं और कीमत भी बहुत कम होती है। जबकि प्राकृतिक रूद्राक्ष हेलोकार्पस गेनीट्रस नामक पेड़ के फल का बीज होता है, जो नेपाल, भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में होता है। आयुर्वेद में इसे औषधीय वनस्पति माना गया है। जबकि इसे गले में धारण करने से दुःखों का निवारण होना माना जाता है। भारत रूद्राक्ष का आयात भी करता है और निर्यात भी। बढ़ती धार्मिक आस्था के चलते रूद्राक्ष का कारोबार भी दिन दूना फल रहा है।

अब आलम यह है कि एक अदद रूद्राक्ष हासिल करने के लिए अंध भक्त हजारों मील दूरी से गिरते पड़ते और अपने खर्चे पर जुटते हैं ताकि रूद्राक्ष पाकर और पंडितजी के दर्शन कर जनम सफल हो जाए। पंडितजी के पास कथावाचन कला के अलावा क्या सिद्धि है, कोई नहीं जानता। पंडितजी की दिलचस्पी भी धार्मिक राजनीतिक अपना आभा मंडल बढ़ाने में है। ऐसे में पंडितजी और उनकी मंडली सिर्फ भीड़ को न्यौतेगी और उस पर नियंत्रण का दायित्व प्रशासन का है। जाम लगे तो पुलिस जाने और जानें गईं तो भगवान जानें। क्योंकि वही कर्ता है, वही करवाता है। तीन लाख में दो-चार निपट भी गए तो कौन सा फर्क पड़ता है। न पंडितजी को, न अंध भक्तों को और न ही प्रशासन और नेताओं को।

संभव है कि कुछ लोग इन मौतों के पीछे भी राजनीतिक एंगल ढूंढें। लेकिन यह किसी राज्य में किसी पार्टी विशेष के शासन का मुद्दा नहीं है। लगभग सभी धार्मिक स्थलों पर बढ़ती बेतहाशा भीड़ और उसके नियंत्रण में प्रशासन और सरकारों की नाकामी, आस्था पर अंधश्रद्धा का काला चश्मा, देश में असली-नकली धार्मिक और आध्यात्मिक बाबाओं की बाढ़ और लोगों का बिना जाने-बूझे उनका गुलाम बन जाना, खुद की जान गंवाकर भी धार्मिक होने और दिखने की आत्मघाती जिद और स्व विवेक को जंग लगे लॉकर में बंद करने की मूर्खतापूर्ण होड़ के कारण यह स्थिति बन रही है। कुछ लोगों का मानना है कि लोग अपनी जिंदगी में विभिन्न समस्याओं, दुखों से इतने परेशान हैं कि उन्हें इन कथा वाचकों और बाबाओं में ही मुक्ति का मार्ग नजर आता है। इसलिए धार्मिक समागमों में भारी भीड़ जुट रही है। लेकिन कोई यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि अदद एक रूद्राक्ष पाने या फिर कोई प्रसाद पाने से सांसारिक कष्टों, विसंगतियों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? व्यक्ति की मुक्ति समाज की मुक्ति का आधार कैसे हो सकती है?

ध्यान रहे कि बीते बीस सालों में मध्यप्रदेश से लेकर केरल तक सैंकड़ों लोग ऐसे धार्मिक समागमों में अपनी जानें गंवा चुके हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि ये मौतें न तो किसी प्राकृतिक आपदा में हुई हैं, न हादसे या किसी रंजिश में हुई हैं। और न ही यह भक्ति के मार्ग में किया गया प्राणोत्सर्ग है। ये अंधी आस्था के पैरों तले कुचली गई अनाम आत्माएं हैं, जो किसी गिनती में नहीं हैं। अगर आंकड़े देखें तो 2005 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंधारदेवी मंदिर मची भगदड़ के दौरान 350 लोगों की जान चली गई थी। 2008 में राजस्थीन के चामुंडा देवी मंदिर में बम की अफवाह के बाद मची अफरा-तफरी में 250 लोग मौत के मुंह में समा गए। इसी साल हिमाचल प्रदेश में नैना देवी मंदिर में मची भगदड़ में 162 लोगों ने असमय अपने प्राण गंवा दिए। 2013 में मप्र के दतिया जिले के रतनगढ़ मंदिर में नवरात्रि उत्सव में 121 श्रद्धालुओं की अकारण बलि चढ़ी। 2011 में केरल के सबरीमाला मंदिर में एक जीप के श्रद्धालुओं पर चढ़ जाने के बाद मची भगदड़ में 104 लोग कुचल कर मर गए। 2012 में पटना में छठ पूजा के दौरान गंगा नदी पर बना अस्थायी पुल टूटने के कारण 20 लोग की मौत हो गई। 2014 में पटना ही के गांधी मैदान में दशहरा उत्सव समाप्ति के ठीक बाद मची अफरा-तफरी में 32 लोग स्वर्गवासी हो गए। यह सिलसिला और भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन बुनियादी सवाल है यह कि क्या यह सच्ची ईश्वर भक्ति है और ऐसी ही अविचारी और निरीह भीड़ से क्या यह देश पुरूषार्थी बन सकता है?

मप्र से विदेशों में एक्सपोर्ट होंगे रेल कोच : सीएम यादव

भोपाल (नप्र)। रायसेन जिले के उमरिया में वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो रेल जैसे अत्याधुनिक रेल कोच बनाए जाएंगे। मप्र में बने रेल कोच दुनियाभर में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। 10 अगस्त को रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखी जाएगी।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। सीएम ने कहा- रक्षाबंधन के 2 दिन पूर्व और 15 अगस्त के 7 दिन पूर्व मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं।

स्वदेशी के भाव से कई कार्यक्रमों की योजना बनाई- सीएम ने कहा- कई कार्यक्रमों की श्रृंखला हमारे द्वारा बनाई गई है और उन कार्यक्रमों

के साथ हमारा मूल भाव इस स्वतंत्रता के पावन पर्व के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वदेशी की भावना को प्रोत्साहन देना है। इसी के तहत हमारे द्वारा कुछ काम किए जाने हैं।

सीएम ने कहा- प्रधानमंत्री जी ने किसान कल्याण, कृषि अर्थव्यवस्था और सारी चीजों को कोट करते हुए जिस प्रकार से स्वदेशी की भावना और खासकर किसान आधारित व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देते हुए अपने देश के अंदर स्वदेशी की भावना को बढ़ावा दिया है।

पहली बार एमपी में बनेंगे रेल कोच- सीएम ने कहा- हमारे मप्र और भोपाल के लिए 10 तारीख स्वदेशीकरण की भावना से महत्वपूर्ण है। हमारे राज्य में पहली बार रेल कोच बनेंगे, मेट्रो ट्रेन बनेगी।

रेल कोच बनाने वाले मैप पर स्थापित होगा एमपी

सीएम ने कहा- प्रदेश में पहली इकाई इस प्रकार के रेल कोच निर्माण करने की सुविधा प्रदान करेगी, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश रेल विनिर्माण के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित होगा।

रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील के उमरिया गांव में 60.630 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हमने कर दिया है। इस उद्योग में वंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रो कोच का निर्माण किया जाएगा। इस उद्योग के लगने से भोपाल और रायसेन जिले में बड़े पैमाने पर सहायक उद्योगों का भी उनकी यूनिटों का भी एक बड़ा बाजार बनेगा। जो मध्य प्रदेश की राजधानी को भी और मध्य प्रदेश को भी अलग-अलग प्रकार के औद्योगिकीकरण से जोड़ने का प्रयास करेगा।